आरक्षित

नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1100

प्रबंधन समिति
दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत
विहार, देहरादून
इसके सचिव कर्नल A.P द्वारा से। कुमेरी (सेवानिवृत्त) श्री
गोपाल दत्त कुमेरी,
सचिव, दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत विहार,
देहरादून

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा से उत्तराखंड राज्य
सिविल सचिवालय, सुभाष रोड
देहरादून
2. अपीलीय प्राधिकरण/सचिव
सहकारी समिति विभाग सचिवालय,
देहरादून
3. श्री विजय कुमार धौंडियाल एस/ओ
ज्ञात नहीं है
वर्तमान में उत्तराखंड, देहरादून
में सहकारी समितियों के
पंजीयक के रूप में तैनात
4. श्री राम गोपाल पुत्र श्री भगवान दास 270/5,
थापर नगर
मेरठ, उत्तर प्रदेश

....प्रतिवादी

वर्तमानः

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंह ।श्री
पूरन सिंह बिष्ट, अतिरिक्त निदेशक ।C.S.C। राज्य
के लिए।
श्री A.S रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री योगेश पचोलिया द्वारा सहायता प्राप्त,
प्रतिवादी नं.4.

लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1101

प्रबंधन समिति
दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत
विहार, देहरादून
इसके सचिव कर्नल A.P द्वारा से। कुमेरी (सेवानिवृत्त) श्री
गोपाल दत्त कुमेरी,
सचिव, दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत विहार,
देहरादून

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा से उत्तराखंड राज्य
   सिविल सचिवालय, सुभाष रोड
   देहरादून
2. अपीलीय प्राधिकरण/सचिव
   सहकारी समिति विभाग सचिवालय,
   देहरादून
3. श्री विजय कुमार धौंडियाल एस/ओ
   ज्ञात नहीं है
   वर्तमान में उत्तराखंड, देहरादून
   में सहकारी समितियों के
   पंजीयक के रूप में तैनात
4. सुशीला शर्मा, श्रीमती श्री राम सरन, टी-15,
   यमुना कॉलोनी, देहरादून
5. श्री गिरीश चंद पुत्र स्वर्गीय श्री विशंभर दत्त निवासी
   <आईडी1>-एडब्ल्यूएचओ, इंदिरा कॉलोनी
   देहरादून

....प्रतिवादी

वर्तमानः

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंह ।श्री
पूरन सिंह बिष्ट, अतिरिक्त निदेशक ।C.S.C । राज्य
के लिए ।
श्री A.S रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री योगेश पचोलिया द्वारा सहायता प्राप्त,
प्रतिवादी नं.5.

<u>लिखित याचिका (एम/एस) सं । 2015 का 1102</u>

प्रबंधन समिति
दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत
विहार, देहरादून
इसके सचिव कर्नल A.P द्वारा से । कुमेरी (सेवानिवृत्त) श्री
गोपाल दत्त कुमेरी,
सचिव, दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत विहार,
देहरादून

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा से उत्तराखंड राज्य
   सिविल सचिवालय, सुभाष रोड
   देहरादून
2. अपीलीय प्राधिकरण/सचिव
   सहकारी समिति विभाग सचिवालय,
   देहरादून
3. श्री विजय कुमार धौंडियाल एस/ओ
   ज्ञात नहीं है

वर्तमान में उत्तराखंड, देहरादून
में सहकारी समितियों के
पंजीयक के रूप में तैनात

4. श्री बाबू राम पुत्र श्री शंभू दयाल निवासी 9/30,
सूर्योदय कॉलोनी
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

....प्रतिवादी

वर्तमानः

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंह।श्री
पूरन सिंह बिष्ट, अतिरिक्त निदेशक।C.S.C। राज्य
के लिए।
श्री A.S रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री योगेश पचोलिया द्वारा सहायता प्राप्त,
प्रतिवादी नं.4.

न्याय

प्रति:रवींद्र मैथानी, जे.

चूँकि इन तीनों रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न निहित है, इसलिए उनका निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य

लिखित याचिका (एम/एस) सं। **2015** का **1100**

2. इस याचिका को उत्तर प्रदेश प्रभावी समिति अधिनियम, 1965 (संक्षेप में, "अधिनियम") की खंड 98 (2) (ए) के तहत पारित दिनांक <आईडी1> के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जो अपील सं. 2013 का 07, दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देहरादून बनाम पंजीयक, प्रभावी समितियाँ और अन्य (संक्षेप में, "अपील")।आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकारी (प्रत्यर्थी सं. 3 इसमें) सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 28.11.2002 के आदेश को बरकरार रखा (पत्र सं. 693/विधि// नि. सा. सा./2002 दिनांक 28 नवंबर, 2002)।पंजीयक ने अपने दिनांक 28.11.2002 के आदेश द्वारा दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, देहरादून की आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

संक्षेप में, "सोसायटी") प्रतिवादी सं. द्वारा निर्माण बढ़ाने के लिए समय बढ़ाने के खिलाफ। 4 राम गोपाल।

3. तत्काल याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों का एक लंबा इतिहास है। यह मुकदमे का तीसरा दौर है।संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) सोसायटी का गठन अधिनियम के तहत अपने सदस्यों को घर आदि के निर्माण के लिए भूमि और अन्य सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। एक प्लॉट जिसमें नं. 117, सोसायटी के चरण-I (इसके बाद "भूखंड" के रूप में संदर्भित) को R.S को आवंटित किया गया था। चुग, जिसने इसे D.P में स्थानांतरित कर दिया। 28.09.1984 पर नांगिया। D.P। नांगिया ने समय पर घर का निर्माण नहीं किया और विस्तार की मांग की, लेकिन उन्होंने एक दशक तक अपना घर नहीं बनाया। सोसायटी द्वारा उन्हें विभिन्न नोटिस जारी किए गए थे।D.P। नांगिया ने मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में एक मुख्तारनामा (पी. ओ. ए.) निष्पादित किया। 07.01.1991 पर नरेश गुप्ता।पी. ओ. ए. के बल पर मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में एक हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित किया। 4 23.07.2001 पर राम गोपाल।इस स्थानांतरण के लिए सोसायटी से कभी अनुमति नहीं ली गई।वास्तव में श्री D.P। पट्टा विलेख के हस्तांतरण के निष्पादन से लगभग 3 साल पहले नांगिया की मृत्यु 13.05.1998 पर हो गई थी।

(ii) 03.11.1993 पर, सोसायटी की प्रबंधन समिति (संक्षेप में, "याचिकाकर्ता") कार्यात्मक नहीं थी और एक प्रशासक नियुक्त किया गया था।प्रशासक ने 03.11.1993 पर प्रतिवादी नं. को स्वीकार किया। 4 राम गोपाल सोसायटी के सदस्य के रूप में।इससे पहले, आई. डी. 1 पर सोसायटी के आम निकाय ने निर्णय लिया था कि किसी भी नए सदस्य का नामांकन नहीं किया जाएगा और आम निकाय के अगले निर्णय तक भूखंड आवंटित नहीं किए जाएंगे।

(iii) याचिकाकर्ता 24.08.2002 पर बिंदु संख्या पर एक प्रस्ताव द्वारा। 4 ने प्रतिवादी सं. की सदस्यता रद्द कर दी।4. प्रबंधन समिति के इस प्रस्ताव को अधिनियम की खंड 128 के तहत पंजीयक द्वारा 28.11.2002 पर अभिखंडित कर दिया गया था। 691/विधि/नीसा। दिनांक 28 नवंबर, 2002)।

(iv) साथ ही, 25.09.2002 पर, याचिकाकर्ता बिंदु संख्या पर एक प्रस्ताव द्वारा। 3 इस बात पर विचार करते हुए कि सोसायटी द्वारा जारी किए गए कई नोटिसों के बावजूद और उपनियम 50 का उल्लंघन करते हुए, प्रतिवादी सं। 4 राम गोपाल ने आवासीय घर का निर्माण कार्य नहीं किया था, भूखंड को फिर से शुरू किया।

(v) ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, प्रतिवादी नहीं। 4 राम गोपाल ने धन जुटाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की

पंजीयक से भूखंड पर निर्माण, जिसे 31.12.2002 तक बढ़ा दिया गया था।समय के इस विस्तार पर सोसायटी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति जताई गई थी:

(a) चूंकि राम गोपाल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.1992 द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अवहेलना करते हुए एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 4 तारीख 24.08.2002, राम गोपाल की सदस्यता पहले ही रद्द कर दी गई थी; और

(b) सोसायटी के रिकॉर्ड में, प्लॉट राम गोपाल के नाम पर दर्ज नहीं किया गया है; प्लॉट D.P को आवंटित किया गया था। नांगिया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और किसी को भी अवैध रूप से भूखंड पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(vi) इन आपत्तियों पर, पक्षों को सुना गया और पंजीयक ने अभिनिर्धारित किया कि जहां तक प्रतिवादी सं. 4 राम गोपाल चिंतित हैं, कि संकल्प सं। 4 दिनांकित 24.08.2002 को पंजीयक द्वारा 28.11.2002 पर पहले ही रद्द दिया गया था, जिसे पत्र सं. 691/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक 28 नवंबर, 2002)।यह भी देखा गया कि इसके पक्ष में निष्पादित स्थानांतरण विलेख पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है

राम गोपाल।तदनुसार, पंजीयक अपने दिनांकित 28.11.2002 आदेश द्वारा (पत्र सं. 693/विधि/नी. सा. सा./2002) दिनांक 28 नवंबर, 2002) ने सोसायटी को प्रतिवादी सं. 4 सोसायटी के अभिलेखों में राम गोपाल और राम गोपाल को स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति दी जाए।आई. डी. 2 दिनांकित इस आदेश को अधिनियम की खंड 98 के तहत अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे शुरू में आई. डी. 1 पर सुनवाई के लिए इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि यह समयबद्ध था और प्रस्ताव अपील के साथ वर्जित नहीं था।

(vii) 21.03.2003 दिनांकित इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (एम/एस) नं. 2003 का 820, प्रबंधन समिति बनाम सचिव और अन्य (संक्षेप ठीक होना, "पहली याचिका"), जिसका निर्णय 22.06.2006 पर याचिकाकर्ता को दोषों को दूर करने के निर्देश के साथ किया गया था ताकि कानून के अनुसार अपील की सुनवाई हो सके।

(viii) पहली याचिका में पारित दिनांक 22.06.2006 के आदेश के अनुसार अपील को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे सहकारी विभाग के सचिव द्वारा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि 29.06.2007 पर समय की वर्जित थी।इस दिनांकित 29.06.2007 आदेश को रिट याचिका (एम/एस) नं. 2007 का 1870, प्रबंधन समिति बनाम।

सहकारी सहकारी विभाग और अन्य (संक्षेप में, "दूसरी याचिका"), जिसे 01.08.2013 पर अनुमति दी गई थी। देरी को माफ कर दिया गया और संबंधित प्राधिकारी को योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।इसके बाद याचिका पर सुनवाई हुई।

(ix) अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने असफल रूप से अपीलीय प्राधिकरण को एक आवेदन दिया कि चूंकि पंजीयक का प्रभार संभालने वाला व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में सहकारी समितियों के सचिव का प्रभार भी संभाल रहा था, इसलिए उसे अपील पर निर्णय लेने से बचना चाहिए।अपील का निर्णय 18.04.2015 पर किया गया था और पंजीयक द्वारा पारित 28.11.2002 के आदेश को बरकरार रखा गया था।इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी।

(x) इस याचिका में, प्रतिवादी एन. ओ. एस. की ओर से। 1, 2 और 3, जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है और, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, यह आपत्ति जताई गई है कि भूखंड को फिर से शुरू करना कानूनी नहीं था और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था; एक व्यक्ति द्वारा एक सक्षम व्यक्ति के पक्ष में विधिवत निर्वहन की गई संपत्ति, जो एक उचित विलेख द्वारा से इसके लिए पूरी तरह से हकदार है, को सोसायटी के उपनियमों के प्रावधानों के तहत फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इसके लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है।प्रतिवादी के अनुसार

एनओएस। 1, 2 और 3, आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तकनीकी मुद्दा को पहले ही निपटा लिया गया है।

(xi) प्रतिवादी नं. 4 ने जवाबी शपथ पत्र भी दायर किया।

इसके अनुसार, नए सदस्य के नामांकन पर प्रतिबंध लगाने वाला सोसायटी के सामान्य निकाय का प्रस्ताव कानून के अनुसार नहीं है; इस प्रस्ताव को कभी भी पंजीयक या अपीलीय प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था; इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दिनांकित आदेश 27.11.1992 पर लागू नहीं था।यह कहा गया है कि दिनांकित 18.04.2015 का आक्षेपित आदेश आत्यन्तिक रूप से उचित है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप का आह्वान करने वाली कोई कानूनी विसंगति नहीं है।

<u>लिखित याचिका (एम/एस) सं। **2015** का **1101**</u>

4. अधिनियम की खंड 98 (2) (ए) के तहत पारित दिनांक <आईडी1> के आदेश के लिए तत्काल याचिका में चुनौती दी गई है। 2013 का 05, दून वैली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, देहरादून बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य।

5. आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी (प्रत्यर्थी सं. 3 इसमें) सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 27.11.2002 के आदेश को बरकरार रखा (पत्र सं.

689/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक 27 नवंबर, 2002) ।पंजीयक ने अपने दिनांक 27.11.2002 के आदेश में बिंदु संख्या पर दिनांकित 14.09.2002 के एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। 2 सोसायटी द्वारा, जिसके द्वारा प्लॉट नं. <आई. डी. 1> प्रतिवादी को आवंटित सं. 4 सुशीला वर्मा को सोसायटी द्वारा फिर से शुरू किया गया।

6. जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं:-

(i) सोसायटी ने प्लॉट नं. आवंटित किया था। 3/1 से D.P। गुप्ता ।D.P। गुप्ता ने प्लॉट को प्रतिवादी नं. 4 श्रीमती. सुशीला शर्मा 01.12.1992 पर और यह सोसायटी की पूर्व अनुमति से किया गया था। श्रीमती. सुशीला शर्मा ने उपनियम 50 के अनुसार तीन साल के भीतर भूखंड पर निर्माण नहीं किया ।उन्हें कई नोटिस, चेतावनी दी गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।

(ii) बिन्दु नं. पर प्रस्ताव पर याचिकाकर्ता। 2 ने 14.09.2002 पर आयोजित अपनी बैठक में भूखंड को फिर से शुरू किया ।यह प्रतिवादी नं. को सूचित किया गया था। 4 श्रीमती. सुशीला शर्मा।

(iii) 14.09.2002 दिनांकित इस प्रस्ताव को 27.11.2002 पर पंजीयक द्वारा रद्द कर दिया गया था ।इसे अधिनियम की खंड 98 के तहत अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे शुरू में इस आधार पर 21.03.2003 पर स्वीकार नहीं किया गया था कि यह समय था

वर्जित और प्रस्ताव अपील के साथ संलग्न नहीं था।

(iv) 21.03.2003 के इस आदेश को पहली याचिका ठीक होना चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय 22.06.2006 पर याचिकाकर्ता को दोषों को दूर करने के निर्देश के साथ किया गया था ताकि कानून के अनुसार अपील की सुनवाई हो सके।

(v) पहली याचिका में पारित दिनांक 22.06.2006 के आदेश के अनुसार अपील को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे समय की वर्जित के आधार पर 29.06.2007 पर फिर से खारिज कर दिया गया था।29.06.2007 के इस आदेश को दूसरी याचिका के साथ चुनौती दी गई थी, जिसकी अनुमति 01.08.2003 पर दी गई थी।देरी को माफ कर दिया गया और संबंधित प्राधिकारी को योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।इसके बाद याचिका पर सुनवाई हुई।

(vi) अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, यह पता चला कि पंजीयक उत्तराखंड राज्य में सहकारी समितियों के सचिव का प्रभार भी संभाल रहे थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने एक असफल आवेदन दायर किया कि सहकारी समितियों के सचिव को अपील पर निर्णय लेने से बचना चाहिए।लेकिन, अपील का फैसला किया गया था

18.04.2015 और पंजीयक द्वारा पारित 27.11.2002 दिनांकित आदेश को बरकरार रखा गया।इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी।

(vii) प्रतिवादी एन. ओ. एस. इस याचिका में 1,2 और 3 ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया है।लिखित याचिका (एम/एस) सं. में उठाई गई आपत्तियाँ। उनके द्वारा भी इस याचिका में 2015 का 1100 मुद्दा उठाया गया है।

(viii) प्रतिवादी नं. 3, जिन्होंने आक्षेपित आदेश पारित किया, उन्होंने भी आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए अलग से जवाबी शपथ पत्र दायर किया।(वास्तव में प्रतिवादी एन. ओ. एस. की ओर से जवाबी शपथ पत्र। 1, 2 और 3 भी प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर किए गए हैं।3.)

(ix) प्रतिवादी नं. 5 गिरीश चंद हैं।वास्तव में, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि भूखंड को फिर से शुरू करने के 10 साल बाद, 19.11.2012 पर, प्रतिवादी नं। 5 गिरीश चंद मैकोटा ने सोसायटी को लिखा कि उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 5 के साथ एक पंजीकृत अनुबंध (लिखित समझौता) निष्पादित किया है। 4 प्लॉट के पट्टे के हस्तांतरण के लिए 25.06.2002 पर और इसलिए, गिरीश चंद मैकोटा प्लॉट के पट्टे के धारक बन गए हैं।

(x) गिरीश चंद मैकोटा ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया है। उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ कहा है कि सोसायटी और प्रथम सदस्य के बीच पहला हस्तांतरण विलेख पूर्ण स्थानांतरण था और विधिवत कानून द्वारा शासित होता है; प्रथम हस्तांतरण विलेख में कोई शर्त नहीं थी कि सदस्य द्वारा निर्माण निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए; सोसाइटी और पट्टा धारक के बीच संबंधों के संबंध में हस्तांतरण विलेख में कोई उल्लेख/निहित खंड नहीं है।यह प्रतिवादी नं द्वारा भी कहा गया है। 5 कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत निहित संपत्ति के अधिकार को केवल एक समाज द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त या रद्द किया जा सकता है; उपनियम कानून नहीं हैं और हर किसी को यह पता नहीं होना चाहिए।

(xi) प्रतिवादी नं. 4 श्रीमती. सुशीला शर्मा को प्रकाशन द्वारा से सेवा प्रदान की गई थी और इसे इस अदालत द्वारा 15.12.2015 पर दर्ज किया गया था, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

<u>लिखित याचिका **(**एम/एस**)** सं। **2015** का **1102**</u>

7. इस याचिका में चुनौती अपील संख्या में पारित अधिनियम की खंड 98 (2) (ए) के तहत पारित दिनांक <आईडी1> के आदेश को दी गई है। 04 का

2013, दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, देहरादून बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य।आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी (प्रत्यर्थी सं. 3 इसमें) सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 28.11.2002 के आदेश को बरकरार रखा (पत्र सं. 692/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक 28 नवंबर, 2002) ।पंजीयक ने अपने दिनांकित 28.11.2002 के आदेश द्वारा प्रस्ताव सं. 4 सोसायटी का दिनांक <आई. डी. 1>, जिस नाम से प्रतिवादी नं. 4 को सदस्यता से हटा दिया गया।

8. याचिका के निपटारे के लिए जिन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(i) प्रतिवादी नं. 4 बाबू राम ने 25.04.1991 पर सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया गया।

(ii) इसके बाद, प्रतिवादी नं। 4 को आवास आयुक्त और कुलसचिव, सहकारी समितियों के रूप में नियुक्त किया गया और पहले के प्रशासक को R.B.S द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। परिहार, आवास विभाग के एक कनिष्ठ कर्मचारी, 12.10.1993 पर।R.B.S की नियुक्ति की तारीख को। परिहार, प्रतीक्षा सूची में 76 सदस्य थे और सभी भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके थे और लगभग पाँच वर्षों से कोई नया सदस्य नामांकित नहीं किया गया था, क्योंकि नए सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं थी।इतना ही नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोसायटी को इससे रोक दिया था।

नए सदस्यों का नामांकन और उन्हें भूखंड आवंटित करने से; सोसायटी के सचिव ने अपने शपथ पत्र में सोसायटी की ओर से आश्वासन दिया था कि किसी भी नए सदस्य का नामांकन नहीं किया जाएगा।याचिकाकर्ता के अनुसार, 18.07.1993 पर, सोसायटी के आम निकाय ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें नए सदस्यों के नामांकन पर रोक लगा दी गई और आम निकाय के अगले निर्णय तक भूखंड के आवंटन को रोक दिया गया।

(iii) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रशासक ने 03.11.1992 पर अवैध रूप से पांच नए सदस्यों का नामांकन किया, जिसमें प्रतिवादी सं. 4 बाबू राम। नए प्रशासक ने 05.02.1994 पर प्लॉट संख्या का आवंटन रद्द कर दिया। सात साल तक प्रतीक्षा सूची में 76 सदस्यों के दावों को नजरअंदाज करते हुए, एक न्यायाधीश गुर्टू को आवंटित किया गया और श्री कृष्ण को आवंटित किया गया।प्रशासक ने तब श्री कृष्ण को पैसे जमा करने और पंद्रह दिनों के भीतर पट्टा विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिया, लेकिन वास्तव में, श्री कृष्ण को कोई जानकारी नहीं भेजी गई थी।इसके बाद, प्रशासक ने 07.03.1994 पर श्री कृष्ण को आवंटित भूखंड को रद्द कर दिया और उसे प्रतिवादी संख्या को आवंटित कर दिया।4.

(iv) प्रशासक द्वारा की गई अवैधता को देखते हुए, जब पहली निर्वाचित समिति अस्तित्व में आई, तो सोसायटी ने सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद

कानून ने प्रतिवादी नं. को नोटिस दिया। 4 और 24.08.2002 पर उनकी सदस्यता हटा दी और उन्हें भूखंड का आवंटन भी रद्द कर दिया।याचिकाकर्ता के 24.08.2002 दिनांकित इस प्रस्ताव को पंजीयक के समक्ष चुनौती दी गई थी।28.11.2002 पर पंजीयक (पत्र सं. 692/विधि।Ni.Sa.Sa./2002 दिनांक 28.11.2002) ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपील की अनुमति दी और सोसायटी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।पंजीयक ने प्रतिवादी सं. को एक वर्ष का समय भी दिया। 4 निर्माण पूरा करने के लिए।

(v) पंजीयक द्वारा पारित इस आदेश को सोसायटी द्वारा अधिनियम की खंड 98 के तहत चुनौती दी गई थी, जिसे शुरू में सचिव, सहकारी समितियों द्वारा सीमा के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था और यह भी कि प्रस्ताव अपील के साथ संलग्न नहीं था।इस आदेश दिनांक 21.03.2003 को याचिकाकर्ता द्वारा पहली याचिका ठीक होना चुनौती दी गई थी, जिसे 22.06.2006 पर याचिकाकर्ता को दोषों को ठीक करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई थी ताकि कानून के अनुसार अपील की सुनवाई हो सके। याचिकाकर्ता ने फिर से अपनी अपील का पीछा किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन सचिव ने 29.06.2007 पर फिर से खारिज कर दिया।

(vi) 29.06.2007 के इस आदेश को दूसरी याचिका के साथ चुनौती दी गई थी, जिसे 01.08.2013 पर अनुमति दी गई थी; देरी को माफ कर दिया गया था और प्राधिकरण

संबंधित को योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।इसके बाद याचिका पर सुनवाई हुई।

(vii) अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण को एक असफल आवेदन दिया कि चूंकि वही व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के पंजीयक के साथ-साथ सहकारी समितियों के सचिव का प्रभार संभाल रहा है, इसलिए उसे अपील पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि इसके बावजूद अपील की सुनवाई की गई और 18.04.2015 पर निर्णय लिया गया।आक्षेपित आदेश द्वारा, पंजीयक द्वारा पारित 28.11.2002 दिनांकित आदेश को बरकरार रखा गया था।इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी।

(viii) प्रतिवादी एन. ओ. एस. 1, 2 और 3 ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया।इसके अनुसार, सोसायटी की सदस्यता खुली सदस्यता है; सदस्यता रद्द करना और भूखंड सं. प्रतिवादी सं. का 182/1। 4 कानूनी नहीं था और कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भी नहीं था; आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है और किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।उत्तरदाता नं. 3 ने प्रतिवादी एन. ओ. एस. की ओर से जवाबी शपथ पत्र दायर किया है। 1, 2 और 3, लेकिन दिलचस्प रूप से उत्तरदाता नहीं। 3 ने अलग-अलग जवाबी शपथ पत्र भी दायर किया (वास्तव में, तीनों याचिकाओं में, उन्होंने ऐसा किया है)।अपने जवाबी शपथ पत्र में, प्रतिवादी नं। 3 ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।

(ix) प्रतिवादी नं. 4 ने जवाबी शपथ पत्र भी दायर किया।

उनके अनुसार, सदस्यता के लिए उनके आवेदन को प्रशासक द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी; इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई स्थगन स्थगन आदेश नहीं था; सामान्य निकाय का दिनांकित निर्णय कानून के अनुसार नहीं था; इसे कभी भी पंजीयक या अपीलीय प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था।आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है।

बहस

9. इन तीनों रिट याचिकाओं में, प्रत्येक याचिका के तथ्यों के संदर्भ में समान बहस दिए गए हैं।

10. न्यायालय अब उन आधारों को ध्यान में रखते हुए मामले पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता है, जिन्हें शुरू में डब्ल्यू. पी. एम. एस. नं. 2015 का 1100, उस रिट याचिका के तथ्यों के साथ।

याचिकाकर्ता के स्वयं पर

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि आक्षेपित आदेश अवैध और अनुचित है, जो एक वैध आदेश के परीक्षण के योग्य नहीं है, इसलिए इसे अभिखंडित जाना चाहिए।विद्वान वकील ने अपनी दलीलों में निम्नलिखित बिंदु उठाए:-

(i) पट्टा विलेख का हस्तांतरण, जो मेजर (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया था। राम गोपाल के पक्ष में 21.07.2001 पर नरेश गुप्ता अमान्य हैं।

(ii) यह हस्तांतरण पी. ओ. ए. दिनांकित <आई. डी. 2> के बल पर किया जाता है, जिसे कथित रूप से <आई. डी. 1> द्वारा निष्पादित किया जाता है। मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में नांगिया। नरेश गुप्ता, लेकिन D.P की मृत्यु पर पी. ओ. ए. पहले ही अपनी वैधता खो चुका था। 13.05.1998 पर नांगिया।

(iii) 13.05.1998 के बाद, पी. ओ. ए. का उपयोग लेन-देन करने के लिए नहीं किया जा सकता था।प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल को दिनांकित पट्टा विलेख के अभिकथित हस्तांतरण के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिला।

(iv) आवंटन के तीन साल के भीतर भूखंड पर कोई निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए भूखंड को फिर से शुरू करना उपनियमों के अनुसार था, जो वैध है।

(v) उप-कानून पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं और अभिकथित हस्तांतरण दिनांक 23.07.2001 उप-कानून 50 से 55 का उल्लंघन करते हुए किया गया है। परिणामस्वरूप प्रबंधन समिति द्वारा भूखंड को फिर से शुरू करना वैध है।

(vi) यदि अधिनियम किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की माँग करता है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए।अधिनियम की खंड 128 के संदर्भ में ऐसा तर्क दिया गया है, जिस पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी।

(vii) प्लॉट सोसायटी के नाम पर है।यह समाज में निहित है।भूखंड को मूल आवंटनकर्ता को भी हस्तांतरित नहीं किया गया था।यह केवल एक पट्टा था, जो आवंटी को दिया गया था।आबंटित व्यक्ति कभी भी भूखंड का पूर्ण स्वामी नहीं बना।

(viii) याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना को दिनांकित 18.04.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने तक सीमित करता है और नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले की रिमांड की प्रार्थना नहीं करता है।

(ix) आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है; न्यायालय को निर्णय लेने में दृष्टिकोण देखना होगा।टाटा सेल्युलर बनाम भारतीय संघ के मामले में निर्धारित सिद्धांत [1]न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का आदेश दें।

12. अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने मोहम्मद मोइनुद्दीन और अन्य बनाम सहकारिता आयुक्त और सहकारिता पंजीयक के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा रखा।समाज [2]..इस मामले के पैरा 40 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> "40. एक बार सर्वेक्षण में भूमि सं। 1 एकड़ के दायरे में 233 और थोकट्टा गाँव में 14 गुंटे सोसायटी द्वारा खरीदे गए थे, यह संपत्ति सोसाइटी में निहित थी।इसलिए, यह सोसायटी को इस बात पर विचार करना है कि सहकारी सिद्धांत और उन उद्देश्यों के अनुसार उक्त भूमि से कैसे निपटा जाए जिनके साथ सोसाइटी का गठन किया गया था, जैसा कि उप-कानूनों में उल्लेख किया गया है।यह व्यक्तिगत सदस्यों का दावा नहीं है कि भूमि को उसके सदस्यों के बीच वितरण के उद्देश्य से किस तरह से निपटाया जाना चाहिए।पुनरावृत्ति के जोखिम पर, यह कहना होगा कि जिन सदस्यों ने सोसायटी को अपनी निधि का योगदान दिया है, उन्हें इस आधार पर संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि उन्होंने भूमि की खरीद के लिए निवेश किया था। इसलिए संस्थापक सदस्यों और बाद में सोसायटी में भर्ती होने वाले सदस्यों दोनों के उक्त दावे को खारिज कर दिया जाता है।"

<u>स्वयं प्रतिवादी नं. **4.**</u>

13. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से नं। 4, यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश वैध है, यह कानून के अनुसार है,

---

[1] (1994) 6 एस. सी. सी. 651
[2] (2014) 8 एस. सी. सी. 661

इसलिए यह किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए:-

(i) मौजूदा रिट याचिका का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता है।यह प्रार्थना आक्षेपित आदेश को रद्द करने और मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए रिमांड तक इस आधार पर सीमित है कि अपीलीय प्राधिकारी अपील पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं था।इसलिए अब सभी मुद्दा को नहीं उठाया जा सकता है।

(ii) एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलीय प्राधिकारी अपील पर निर्णय लेने के लिए निहित था।अन्य तथ्यात्मक पहलुओं की जांच नहीं की जा सकती है; रिट याचिका में शीर्षक की जांच नहीं की जा सकती है।इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता दीवानी अदालत का रुख कर सकता है।

(iii) D.P। नांगिया ने मेजर (सेवानिवृत्त) के विचार के लिए पी. ओ. ए. को निष्पादित किया था। नरेश गुप्ता।यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता D.P के रिश्तेदार नहीं हैं। नहीं, यह माना जाना चाहिए कि कुछ विचार किया जा रहा है।

(iv) पी. ओ. ए. विचार के लिए अपरिवर्तनीय है।विल के साथ अपरिवर्तनीय पी. ओ. ए. अपने निष्पादक की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता है; स्थायी पट्टे में हस्तांतरण का एक तत्व होता है।

(v) निष्पादक की मृत्यु पर, पी. ओ. ए. समाप्त नहीं होता है।मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता की भूखंड में रुचि है और इस मामले में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 202 (संक्षेप में, "अनुबंध अधिनियम") के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है, और साथ ही भूखंड की खंड 208 के प्रावधान को भी शामिल किया जाता है।

अनुबंध अधिनियम लागू होता है।जब तक कि मेजर (सेवानिवृत्त) द्वारा निष्पादित स्थानांतरण विलेख न हो। प्रतिवादी नं. के पक्ष में नरेश गुप्ता। 4 राम गोपाल को रद्द कर दिया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में विलेख को न तो अभिखंडित जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है।

(vi) प्रतिवादी नं। 4 राम गोपाल के पास भूखंड पर कानूनी अधिकार हैं; उन्होंने इसे एक हस्तांतरण विलेख द्वारा से प्राप्त किया, जिसे अभी तक रद्द नहीं किया गया है।

(vii) सोसायटी ने अपने सदस्यों द्वारा से भूखंड खरीदे और प्रत्येक सदस्य को पट्टे पर दिए।प्रत्येक सदस्य का संपत्ति पर अधिकार निहित है।

(viii) एक बार प्लॉट स्थानांतरित हो जाने के बाद, एक सदस्य इसका मालिक बन जाता है।

उपनियम भूखंड के हस्तांतरण को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में, "T.P") का प्रावधान। एक्ट ") चलन में आएगा।

(ix) तत्काल मामले में, स्थायी पट्टा एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो सदस्य बनने का पात्र है।

(x) उप-कानून कानून नहीं हैं।अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में उप-कानून के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है; उप-कानून अधिनियम से ऊपर नहीं हो सकते हैं।

(xi) उपनियम 55 का प्रावधान खराब है, जो एक सदस्य द्वारा भूखंड के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है।

(xii) सोसायटी ने उचित रूप से प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल को सोसायटी के सदस्य के रूप में 03.11.1993 पर क्योंकि उस तारीख को उच्च न्यायालय का कोई आदेश लागू नहीं था।

(xiii) सोसायटी के प्रशासक के पास सदस्यों को शामिल करने की शक्ति है।सदस्य का निष्कासन सामान्य निकाय के पास होना चाहिए न कि प्रबंधन समिति के पास।

(xiv) उपनियमों में भूखंड को फिर से शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

14. उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने भगवानभाई करमनभाई भारवाद बनाम आरोग्यनगर को-ऑप के मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा रखा।हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य [3]; द्वारका प्रसाद अग्रवाल (डी) <आईडी1> द्वारा। और एक और बनाम. B.D। अग्रवाल और अन्य [4]; सत्य पाल आनंद बनाम राज्य M.P। & अन्य।[5]; पनियाला श्रम सम्विद सहकारी समिति लिमिटेड बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य [6]; और बी. अंजनेयुलु बनाम V.G। रघुनाथन [7] हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य [8]; और रमेश चंद बनाम सुरेश चंद और अन्र। [9]..

15. भगवानभाई करमनभाई भरवाड़ (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि "चूंकि किसी भी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण के अमान्य कार्यों को घोषित नहीं किया गया था**,** इसलिए इसे वैध माना जाएगा।**...**"।

---

[3] ए. आई. आर. 2003 गुज-294
[4] ए. आई. आर 2003 एस. सी. 2686
[5] (2016) 10 एससीसी 767
[6] 2008 (3) यूसी 1896
[7] 1995 (1) ALT 131
[8] (2014) 6 एससीसी 1
[9] आईएलआर (2012) बनाम दिल्ली 48 आरएफए

16. द्वारका प्रसाद अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे और प्रयोग करने की सीमा की व्याख्या की।यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:-

> "28. सार्वजनिक कानून उपाय में एक रिट याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता से संबंधित है।कला के तहत उपाय भारत के संविधान की धारा 226 को किसी निजी कानून विवाद के समाधान के लिए उपयोग करना नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सार्वजनिक कानून के चरित्र से जुड़े विवाद से अलग है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि संपत्ति या स्वामित्व विवाद के समाधान के लिए कोई रिट उपाय उपलब्ध नहीं है।निर्विवाद रूप से, पक्षों के बीच बड़ी संख्या में निजी विवाद और विशेष रूप से यह सवाल कि क्या हस्तांतरण का कोई विलेख मेसर्स राइटर एंड पब्लिशर्स पं. लिमिटेड के साथ-साथ यह भी कि विभाजन या तमलिक नामा हुआ था या नहीं, सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालयों के समक्ष अधिनिर्णयन लंबित होना थे।रिट याचिका में मांगी गई राहत मुख्य रूप से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में प्रतिवादीओं में से एक द्वारा की गई घोषणा के प्रमाणीकरण के आदेश के इर्द-गिर्द घूमती थी। रिट याचिका, मामले में निहित तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, केवल उस उद्देश्य के लिए बनाए अनुरक्षणीय माना जा सकता था और कोई अन्य नहीं।"

17. सत्यपाल आनंद (ऊपर) के मामले में, सहकारी समिति ने एक भूखंड को रद्द कर दिया था।मृतक सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा विभिन्न मुकदमे दायर किए गए थे।ऐसी स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ टिप्पणी की:-

> "45. इस मामले में मुख्य सवाल यह है:क्या सोसायटी द्वारा भूखंड के आवंटन को रद्द करने और उसके बाद एक बुझाने के विलेख को निष्पादित करने की कार्रवाई एक न्यायसंगत कार्रवाई थी?इस पर 1960 के अधिनियम के प्रावधानों और सोसायटी के उपनियमों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए जो सोसाइटी के सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं।अनुबंध अधिनियम और विशिष्ट राहत अधिनियम और सहकारी कानूनों और सोसायटी के उप कानूनों के प्रावधानों की परस्पर क्रिया, जो भूखंड के आवंटन को रद्द करने या संबंधित सदस्य की सदस्यता की अनुमति देते हैं, पर उचित कार्यवाही में विचार करना होगा।क्या सोसाइटी का अपने सदस्य के पक्ष में किए गए भूखंड के आवंटन को रद्द करने का निर्णय परिसीमा अधिनियम के कानून द्वारा वर्जित है, यह फिर से सहकारी मंच के समक्ष कार्यवाही में परीक्षण किया जाने वाला मामला है जहां अपीलकर्ता द्वारा एक विवाद दायर किया गया है, यदि अपीलकर्ता उस दलील का पालन करता है।

> 47. मौजूदा मामले में, सम्बंधित दस्तावेज़ को निस्संदेह एक अग्निशामक विलेख कहा जाता है।हालांकि, वास्तव में, यह संबंधित सदस्य द्वारा दायित्व को पूरा न करने के कारण अपने सदस्य को दिए गए विषय भूखंड के आवंटन को रद्द करने के सोसायटी के निर्णय की अभिव्यक्ति है।विषय दस्तावेज हाउसिंग सोसाइटी द्वारा आवंटित भूखंड की सदस्यता को रद्द करने के सोसायटी के निर्णय से जुड़ा हुआ है।दूसरे शब्दों में, यह सोसायटी का निर्णय है, जिसे सोसाइटी शासी सहकारी कानूनों और उप-कानूनों के ढांचे के भीतर प्रयोग करने का हकदार है जो सोसाइटी के सदस्यों पर बाध्यकारी हैं।थोटा गंगा लक्ष्मी का मामला [थोटा गंगा लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ A.P., (2010) 15 SCC 207: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1063], इस तथ्य के अलावा कि यह सांविधिक नियम, अर्थात् आंध्र प्रदेश पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 26 (के) (आई) में निहित एक स्पष्ट प्रावधान के साथ काम कर रहा था, हाउसिंग सोसाइटी द्वारा भूखंड के आवंटन को रद्द करने के लिए एक विलेख का मामला भी नहीं था।लेकिन, निजी पक्षों के बीच निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने का, जिसे एकतरफा रूप से रद्द करने की मांग की गई थी।यहां तक कि बाद के कारण से भी थोटा गंगा लक्ष्मी [थोटा गंगा लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ A.P., (2010) 15 SCC 207:(2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1063] का मौजूदा मामले की तथ्य परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"

18. पनियाला श्रम सम्विद सहकारी समिति लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह निर्णय दिया कि "एक वैधानिक कल्पना द्वारा, प्रशासक को प्रबंधन समिति की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं और इस प्रकार प्रशासक के पास नए सदस्यों को भी नामांकित करने की शक्ति है।"

19. बी. अंजनेयुलु (उपरोक्त) के मामले में, हाउसिंग सोसाइटी का एक सदस्य एक भूखंड बेचने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बाद में इस आधार पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया कि खरीदार एक रक्षा कर्मी नहीं था, जो केवल सोसाइटी के उपनियम 5 और 11 को देखते हुए भूखंड खरीद सकता था।उन परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "एक बार जब सोसायटी अपने सदस्य के पक्ष में संपत्ति बेच देती है, तो सदस्य संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन जाता है और वह जिसे चाहे उसे हस्तांतरित कर सकता है और इसी तरह कोई भी व्यक्ति इसे अपने आवास के लिए खरीद सकता है।

उद्देश्य।अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि उपनियम सं। **5** और **11** उसी को प्रतिबंधित करते हैं।आत्यन्तिक रूप**,** मेरी राय में**,** बाय-लॉ नंबर। **5** और **11** का समाज के किसी सदस्य के अपनी संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को अर्जित करने के बाद उसे स्वामित्व बदलनाने के अधिकार से कोई संबंध नहीं है।इस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि उपनियम कोई कानून नहीं हैं, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सभी को यह पता होना चाहिए।

20. हर्षद गोवर्धन सोंडागर (ऊपर) के मामले में, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नं। 4 ने कानून के प्रावधानों का उल्लेख किया, जैसा कि निर्णय में चर्चा की गई है, यह तर्क देने के लिए कि पट्टा T.P के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। एक्ट करें। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टी. पी. अधिनियम की खंड 111 की व्याख्या करते हुए कहा कि "जब तक किसी अचल संपत्ति का पट्टा निर्धारित नहीं होता है**,** तब तक पट्टेदार को संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार है और यह अधिकार संपत्ति का अधिकार है और इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद **300-**ए में प्रदान किए गए कानून के अधिकार के बिना नहीं लिया जा सकता है।"

21. रमेश चंद (उपरोक्त) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम की खंड 202 के प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि निष्पादक की मृत्यु के बाद भी विचार के लिए दिए गए मुख्तारनामा वैधता देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत पात्रता बनी रहे क्योंकि यह एक नियमित या नियमित पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है**,** बल्कि एक ही है।

एक वाणिज्यिक लेन-देन के तत्व हैं जिन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादक की मृत्यु के कारण निराश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बेहलफ ऑफ द स्टेट

22. राज्य की ओर से कोई बहस नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता के स्वयं के बारे में जवाब दें

23. प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाई गई बहस का जवाब देना। 4, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि पट्टे पर देने वाला हमेशा सोसायटी रहा है।वास्तव में, D.P के पक्ष में आवंटन। नांगिया ने यह भी निर्धारित किया है कि किसी भी हस्तांतरण से पहले सोसायटी की अनुमति लेनी होगी।यह तर्क दिया जाता है कि सोसायटी के सदस्य उपनियमों और प्रतिवादी सं. सं. के पक्ष में हस्तांतरण पट्टा विलेख जैसे एक शून्य दस्तावेज से बंधे हैं। 4 को नजरअंदाज किया जा सकता है।

24. उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य के मामले में फैसले पर भरोसा किया है। [10.] , जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि "शून्य" अभिव्यक्ति के कई पहलू हैं।एक प्रकार के अमान्य कार्य, लेन-देन, फरमान वे हैं जो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, आरम्भतः ही अमान्य हैं और उनसे बचने के लिए किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है।

मूल याचिकाओं में पूर्व निर्णय

[10] आकाशवाणी 2001 एससी 2552

25. तत्काल याचिकाओं पर एक बार इस न्यायालय द्वारा 06.07.2018 पर निर्णय लिया गया था।उस तारीख को, याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि पंजीयक अधिनियम की खंड 128 को देखते हुए सोसायटी को इस पर पुनर्विचार करने की अनुमति दिए बिना प्रबंधन समिति के प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकता था, जो अनिवार्य है।इस तर्क को स्वीकार करते हुए, आक्षेपित आदेश और पंजीयक के आदेश को रद्द दिया गया और मामले को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए सोसायटी को वापस भेजने के निर्देश के साथ पंजीयक को वापस भेज दिया गया।रिट याचिका में पारित 06.07.2018 के इस आदेश को विशेष अपील सं. 2018 का 686 (संक्षेप में, "विशेष अपील"), जिसे 06.03.2019 पर अनुमति दी गई थी।विशेष अपील में, न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया:-

> "12. यद्यपि खंड 126 का परंतुक अनिवार्य या निर्देशिका है या नहीं, इस पर निष्कर्ष राय दर्ज करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन हमने न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर केवल यह ध्यान दें के लिए ध्यान दिया है कि केवल "होगा" शब्द का उपयोग, अपने आप में, उक्त परंतुक को अनिवार्य नहीं बनाएगा, और न ही परिणाम का उल्लेख करने में विफलता, अपने आप में और बिना किसी और चीज़ के, इसे निर्देशिका बना देगी।
>
> 13. जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री A.S रावत और प्रतिवादी-लिखित याचिका के विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ सिंह दोनों द्वारा आग्रह किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच नहीं की है। इसलिए हम अपील के तहत आदेश को रद्दना और रिट याचिकाओं को दाखिल करने के लिए बहाल करना उचित समझते हैं।यह दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है ताकि आज की स्थिति को अगले आदेश तक बनाए रखा जा सके।यह आदेश रिट याचिका में अंतरिम आदेश होगा।
>
> 14. अनिश्चित दलीलें पूरी हो चुकी हैं, इसमें अपीलकर्ताओं के लिए यह खुला है कि वे या तो विद्वान एकल न्यायाधीश से बारी-बारी से सुनवाई के लिए रिट याचिकाओं पर विचार करने का अनुरोध करें या अंतरिम आदेश को हटाने की मांग करें।"

26. विशेष अपील में फैसले के बाद मामले की नए सिरे से सुनवाई की जाती है।

<u>तत्काल याचिकाओं का दायरा</u>

27. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में फैसले को देखते हुए इस मामले में निर्णय लेने की आदेशिका, अवैधता, तर्कहीनता जैसे मुद्दा की जांच की जानी चाहिए।यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय, वास्तव में, प्रशासनिक मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे को परिभाषित करता है।इन सिद्धांतों पर आगे गोहिल विश्वराज हनुभाई के मामले में चर्चा की गई। [11], जहाँ पैरा एन. ओ. एस. में है। 15, 16 और 17 में, न्यायालय ने पहले के कानूनों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर कानून पर चर्चा की, जो कि नीचे दिया गया है:

> "15. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से तय किए गए हैं।इस संबंध में अक्सर उद्धृत किए जाने वाले दो निर्णय एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम।वेड्सबरी कॉर्प.[एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम।वेड्सबरी कॉर्प., (1948) 1 के. बी. 223 (सी. ए.)] और सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री [सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, 1985 अधिनियम *374:(1984) 3* डब्ल्यू. एल. आर. 1174:(1984) 3 सभी ईआर 935 (एचएल)]।
> 16. लॉर्ड डिप्लॉक ने सिविल सेवा संघों की परिषद [सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, *1985* अधिनियम *374* में अपनी प्रसिद्ध राय में कहा:(1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1174:(1984) 3 ऑल ई. आर. 935 (एच. एल.)] ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:(एसी पी।410 डी-एच और 411 ए-बी)
> ".....पहला आधार जिसे मैं "अवैधता", दूसरा "तर्कहीनता" और तीसरा "प्रक्रियात्मक अनुचितता" कहूंगा।इसका मतलब यह नहीं है कि मामले-दर-मामले के आधार पर आगे का विकास समय के साथ और आधार नहीं जोड़ सकता है।मेरा ध्यान विशेष रूप से भविष्य में "आनुपातिकता" के सिद्धांत को संभावित रूप से अपनाने पर है, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक व्यवस्था में मान्यता प्राप्त है, लेकिन तत्काल मामले को निपटाने के लिए तीन पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित प्रमुख जिनका मैंने उल्लेख किया है, वे पर्याप्त होंगे।
> "अवैधता" से, न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में, मेरा मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए।उसके पास उत्कृष्टता है या नहीं, यह एक न्यायोचित प्रश्न है जिसका निर्णय विवाद की स्थिति में उन लोगों द्वारा किया जाता है।

[11] (2017) 13 एस. सी. सी. 621

व्यक्ति, न्यायाधीश, जिनके द्वारा राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

"अतार्किकता" से मेरा मतलब है कि अब तक जिसे संक्षिप्त रूप से "वेड्सबरी अतार्किकता" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है (एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम।वेड्सबरी कॉर्प.*[*एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम। वेड्सबरी कॉर्प., (1948) 1 KB 223 (CA)])।यह एक ऐसे निर्णय पर लागू होता है जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवज्ञा में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया था, उस पर नहीं पहुंच सकता था। क्या कोई निर्णय इस श्रेणी में आता है, यह एक ऐसा सवाल है कि न्यायाधीशों को अपने प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, अन्यथा हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ गलत होगा।अदालत द्वारा इस भूमिका के प्रयोग को सही ठहराने के लिए, मुझे लगता है कि आज एडवर्ड्स *(*कर निरीक्षक*)* बनाम बेयरस्टो [एडवर्ड्स *(*कर निरीक्षक) बनाम बेयरस्टो, *1956* एसी *14* में विस्काउंट रैडक्लिफ के सरल स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है:(1955) 3 डब्ल्यूएलआर 410 (एचएल)]

निर्णय निर्माता द्वारा कानून की एक अनुमानित लेकिन अज्ञात गलती के लिए इसे जिम्मेदार ठहराकर अदालत द्वारा किसी निर्णय को उलटने के लिए एक आधार के रूप में अतार्किकता।अब तक "अतार्किकता" एक स्वीकृत आधार के रूप में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है जिस पर न्यायिक समीक्षा द्वारा किसी निर्णय पर हमला किया जा सकता है।

मैंने तीसरे शीर्ष को प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करने में विफलता या निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के प्रति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ कार्य करने में विफलता के बजाय "प्रक्रियात्मक अनुचितता" के रूप में वर्णित किया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शीर्ष के तहत न्यायिक समीक्षा की संवेदनशीलता एक प्रशासनिक अधिकरण द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने में विफलता को भी शामिल करती है जो उस विधायी साधन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं जिसके द्वारा इसकी अधिकार क्षेत्र प्रदान की गई है, भले ही ऐसी विफलता में प्राकृतिक न्याय का कोई इनकार शामिल न हो।लेकिन तत्काल मामला प्रशासनिक अधिकरण की कार्यवाही से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।"

यह उपरोक्त उद्धरण से देखा जा सकता है, लॉर्ड डिप्लॉक ने तीन प्रमुखों की पहचान की जिनके तहत न्यायिक समीक्षा की जाती है। अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता।उन्होंने भविष्य में "आनुपातिकता" जैसे नए प्रमुखों की पहचान की संभावना को भी पहचाना।उन्होंने पहले से ही पहचाने गए तीन प्रमुखों की अवधारणाओं को समझाया।उन्होंने घोषणा की कि सिर "अतार्किकता" "वेड्सबरी अतार्किकता" का पर्याय है।

17. सिविल सेवा संघ परिषद [सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, *1985* अधिनियम *374* में निर्धारित सिद्धांत:*(1984) 3* डब्ल्यू. एल. आर. 1174:(1984) 3 टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ [टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651] और सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) *6* एस. सी. सी. *651]* में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ सभी ई. आर. *935 (*एच. एल.*)* को उद्धृत किया गया है।भारत संघ *[*सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम.भारत संघ, *(2008)* 16 एस. सी. सी. 215:ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1204]

28. तत्काल मामले में, व्यक्तियों के अधिकार तब निहित थे जब कुलसचिव द्वारा

दिनांकित 28.11.2002 आदेश पारित किया गया था और

जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश के नागरिक परिणाम थे।प्लॉट को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल को रद्द कर दिया गया।दोनों के नागरिक परिणाम थे।

29. ये याचिकाएं सरशियोरेराई की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई हैं।याचिकाकर्ता की ओर से जो तर्क दिया गया है वह यह है कि मामले में निर्णय लेने की आदेशिका, अवैधता, तर्कहीनता की जांच की जानी चाहिए।टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया है।

30. जैसा कि कहा गया है, टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में, न्यायिक समीक्षा और कार्यकारी कार्यप्रणाली के दायरे की व्याख्या की गई है और कहा गया है।इन सिद्धांतों को गोहिल विश्वराज हनुभाई (उपरोक्त) के मामले में दोहराया गया है।यह प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित है।सवाल यह है:क्या आक्षेपित आदेश एक प्रशासनिक कार्रवाई है?

31. न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या विशुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई हालांकि अलग हैं, लेकिन हाल के दिनों में, एक प्रशासनिक कार्रवाई और अर्ध-न्यायिक कार्रवाई के बीच का अंतर इस हद तक धुंधला हो गया है कि कभी-कभी वे एक ही प्रतीत होते हैं।

32. T.C के मामले में। बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और एक अन्य[12.], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेक्स बनाम बिजली आयुक्त के फैसले से उद्धृत किया [13.] विशुद्ध रूप से मंत्रिस्तरीय कार्यों और अर्ध-न्यायिक कार्यों के बीच अंतर करना, जैसा कि नीचे दिया गया है:

> "7. सरशियोरेराई की रिट जारी करने के संबंध में मौलिक सिद्धांतों में से एक यह है कि रिट का लाभ केवल न्यायिक अधिनियमों की वैधता को हटाने या न्याय निर्णय लेने के लिए लिया जा सकता है।"न्यायिक कार्य" शब्द में प्रशासनिक निकायों या अन्य प्राधिकरणों या ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य व्यक्तियों द्वारा अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग शामिल है और इसका उपयोग विशुद्ध रूप से मंत्रिस्तरीय कार्यों के विपरीत किया जाता है।एटकिन, L.J। इस प्रकार रेक्स बनाम विद्युत आयुक्तों [(1924) *1* के. बी. 171 205 पर] में इस बिंदु पर कानून का सारांश दिया गया है:
> "जब भी कोई व्यक्ति या व्यक्ति जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारण का कानूनी अधिकार रखता है और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य रखता है, अपने कानूनी अधिकार से अधिक कार्य करता है, तो वे इन रिटों में प्रयोग किए गए राजा के पीठ डिवीजन के नियंत्रण अधिकार क्षेत्र के बशर्ते होते हैं।"
> सरशियोरेराई की दूसरी आवश्यक विशेषता यह है कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायालयों या निकायों पर इसद्वारा से जो नियंत्रण प्रयोग किया जाता है, वह अपीलीय नहीं बल्कि पर्यवेक्षी क्षमता में होता है। सरशियोरेराई की रिट देने में उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है।यह उन साक्षयों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिन पर निम्न अधिकरण का निर्धारण आधारित होने का अर्थ लगाना है।यह उस आदेश को ध्वस्त करता है जिसे वह अधिकार क्षेत्र के बिना या स्पष्ट रूप से गलत मानता है, लेकिन अपने स्वयं के विचारों को निम्न अधिकरण के विचारों प्रतिस्थापित पर नहीं रखता है।ऐसा कहने के लिए अपमानजनक आदेश या कार्यवाही को रास्ते से हटा दिया जाता है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए नहीं किया जाना चाहिए [वालशॉल के ओवरसियर बनाम लंदन और उत्तर पश्चिमी रेलवे कंपनी, *(1879) 4* एसी 30 में लॉर्ड केर्न्स के अनुसार।39.] ..
> "

33. सर्टिओरारी के दायरे सरशियोरेराई व्याख्या आगे T.C के मामले में सरशियोरेराई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बसप्पा (ऊपर दिया गया):-

> "8. जैसा कि लॉर्ड समर द्वारा किंग बनाम नैट बेल लिकर लिमिटेड [(1922) 2 एसी 128,156] में व्यक्त किया गया है, सरशियोरेराई के रिट द्वारा से प्रयोग की जाने वाली वरिष्ठ अदालत की देखरेख दो बिंदुओं पर होती है।एक निम्न अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र और इसके अभ्यास की योग्यता और शर्तें हैं; दूसरा पाठ्यक्रम में कानून का पालन है।

---

[12] आकाशवाणी 1954 एससी 440
[13] (1924) 1 (के. बी.) 171 205 पर

> अपने अभ्यास से।ये दोनों प्रमुख आम तौर पर उन सभी आधारों को शामिल करते हैं जिन पर सरशियोरेराई की रिट की मांग की जा सकती है।वास्तव में सिद्धांतों के उच्चारण में बहुत कम कठिनाई होती है; किसी विशेष मामले के तथ्यों पर सिद्धांतों को लागू करने में वास्तव में कठिनाई उत्पन्न होती है।
>
> 9. सरशियोरेराई झूठ बोल सकता है और आम तौर पर तब दिया जाता है जब किसी अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य किया हो।अधिकार क्षेत्र की कमी कार्यवाही के विषय-वस्तु की प्रकृति या कुछ प्रारंभिक कार्यवाही की अनुपस्थिति में से उत्पन्न हो सकती है या न्यायालय स्वयं कानूनी रूप से गठित नहीं हो सकता है या बाहरी परिस्थितियों के कारण कुछ अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। IX,पी. 880]।जब न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी संपार्श्विक तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, तो यह अच्छी तरह से तय हो जाता है कि न्यायालय तथ्य के गलत निर्णय से उसे ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता है जो अन्यथा उसके पास नहीं होगा [वीडियो बैनबरी बनाम फुलर, *9* एक्सच।*111;* आर बनाम आयकर विशेष उद्देश्य आयुक्त, 21 क्यू. बी. डी. 313]।"

34. इसी तरह के सिद्धांतों को आगे दोहराया गया था A.K। क्राईपाक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [14] ..इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में प्रशासनिक शक्ति और अर्ध-न्यायिक शक्ति के बीच विभाजन रेखा की व्याख्या इस प्रकार की:-

> "13. प्रशासनिक शक्ति और अर्ध-न्यायिक शक्ति के बीच विभाजन रेखा काफी कम है और धीरे-धीरे समाप्त की जा रही है।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति है या अर्ध-न्यायिक शक्ति है, किसी को प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, जिस व्यक्ति या व्यक्ति को यह प्रदान की गई है, उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून की रूपरेखा, उस शक्ति के प्रयोग से होने वाले परिणाम और उस शक्ति का उपयोग करने के तरीके को देखना होगा।हमारे संविधान के तहत कानून का शासन प्रशासन के पूरे क्षेत्र में व्याप्त है।हमारे संविधान के तहत राज्य का प्रत्येक अंग कानून के शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित होता है।हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अपरिहार्य है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।कानून के शासन की अवधारणा अपनी जीवंतता खो देगी यदि राज्य के साधनों को अपने कार्यों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से करने का कर्तव्य नहीं दिया जाता है।सार में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता और कुछ नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है न कि मनमाने ढंग से या मनमौजी रूप से। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निहित मानी जाने वाली प्रक्रियाएं केवल वे हैं जो एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित नहीं करती हैं।हाल के वर्षों में अर्ध-न्यायिक शक्ति की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है।जिसे कुछ साल पहले एक प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, अब उसे अर्ध-न्यायिक शक्ति माना जा रहा है।द.

---

[14] (1969) 2 एससीसी 262

> लार्ड पार्कर *C.J* की टिप्पणियों के बाद, रेजिना बनाम आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड एक्स एकपक्षीय लेन [(1967) 2 क्यूबी 864 पी।881] शिक्षाप्रद हैं।"मिस्टर ब्रिज के दूसरे बिंदु के संबंध में मुझे नहीं लगता कि एटकिन ने अपने सिद्धांत को उन मामलों तक सीमित रखने का इरादा किया था जिनमें निर्धारण ने लागू करने योग्य अधिकारों के अर्थ में अधिकारों को प्रभावित किया था।वास्तव में, विद्युत आयुक्तों के मामले में निर्धारित अधिकार किसी भी तरह से तत्काल लागू करने योग्य अधिकार नहीं थे क्योंकि आयुक्तों द्वारा निर्धारित योजना को परिवहन मंत्री और संसद के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित किया जाना था।फिर भी आयुक्तों को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।इसके एकपक्षीय जैसा कि रेक्स बनाम पोस्टमास्टर-जनरल एक्स पार्टी कारमाइकल [(1928) 1 KB 291] और रेक्स बनाम बॉयकॉट एक्स पार्टी केसले [(1939) 2 KB 651] से देखा जा सकता है कि उपाय उपलब्ध है, भले ही निर्णय केवल एक कदम है जिसके परिणामस्वरूप कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
>
> जैसा कि मैं देख रहा हूं कि स्थिति यह है कि प्राचीन उपाय की सटीक सीमाओं को कभी भी विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और न ही सरशियोरेराई चाहिए।वे समय-समय पर बदलती परिस्थितियों को पूरा करने के लिए विस्तारित किए जाते रहे हैं।एक समय में रिट केवल एक निचली अदालत में जाती थी, बाद में इसका दायरा कानूनी न्यायालयों तक बढ़ा दिया गया था जो एक पक्षों के बीच का निर्णय करते थे।बाद में फिर से इसका विस्तार उन मामलों में किया गया जहां शब्द के सख्त अर्थ में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जहां किसी नागरिक के तत्काल या बाद के अधिकार प्रभावित हुए थे।एकमात्र स्थिर सीमा यह थी कि यह एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा था।निजी या घरेलू न्यायालय हमेशा सरशियोरेराई के दायरे से बाहर रहे हैं क्योंकि उनका अधिकार पूरी तरह से अनुबंध से, यानी संबंधित पक्षों के इकरारनामा से प्राप्त होता है।
>
> अंत में, यह देखा जाना चाहिए कि उपाय को अब बढ़ा दिया गया है, रेग देखें। वी.मैनचेस्टर कानूनी सहायता समिति, पूर्व एकपक्षीय *R.A*। ब्रांड एंड कंपनी लिमिटेड [(1952) 2 क्यू. बी. 413] उन मामलों में जिनमें एक प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक चरित्र की जांच या आदेशिका के बाद ही लिया जाता है।ऐसे मामले में इस अदालत के पास उस आदेशिका की निगरानी करने का अधिकार क्षेत्र है।

35. महाप्रबंधक, विद्युत रेंगली पनबिजली परियोजना, उड़ीसा और अन्य बनाम गिरिधारी साहू और अन्य के मामले में [15.] , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इशाक के मामले में निर्धारित प्रस्ताव को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। [16.] सरशियोरेराई के संबंध में, जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है:

> "21. हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक *[*हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:(एयर पीपी। 243-44, पैरा 21 &23)

---

[15] (2019) 10 एस. सी. सी. 695

[16] आकाशवाणी 1955 एस. सी. 233

"21. ... इन प्राधिकरणों पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित के रूप में लिया जा सकता है:(1) अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए सरशियोरेराई जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई निम्न न्यायालय या अधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है।(2) सरशियोरेराई तब भी जारी किया जाएगा जब न्यायालय या अधिकरण अपनी निस्संदेह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।(3) सरशियोरेराई की रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में।इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय निचली अदालत या अधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के परिणाम की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों।यह इस सिद्धांत पर है कि एक अदालत जिसके पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है, उसे गलत और सही दोनों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, और जब विधायिका उस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो यह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई उच्च न्यायालय साक्षय के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करता है, और अपने स्वयं के परिणाम को सरशियोरेराई में प्रतिस्थापित करता है।ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किए गए हैं और विवाद में नहीं हैं।

* * *

23. इसलिए यह तय माना जा सकता है कि कानून की त्रुटि को ठीक करने के लिए सरशियोरेराई का एक रिट जारी किया जा सकता है।लेकिन यह आवश्यक है कि यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक हो*;* यह ऐसा होना चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट होना चाहिए।...
तथ्य यह है कि अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि को सटीक या संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति में अनिश्चितता का एक तत्व निहित है, और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

"

36. गिरिधारी साहू (उपरोक्त) के मामले में इस मुद्दे पर कानून पर चर्चा करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरशियोरेराई जारी करने के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

"28. निर्णयों और सामग्री के संदर्भ में, हम निम्नानुसार मानेंगे:सरशियोरेराई की रिट जारी करने की अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी है न कि अपीलीय।सरशियोरेराई के रिट आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय अपील न्यायालय की सीमा नहीं लेगा।यह सबूतों की फिर से सराहना नहीं करेगा।सर्टिओरारी के रिट का उद्देश्य अधिकार क्षेत्र की ज्यादतियों को ठीक सरशियोरेराई है।निषेध का एक रिट तब जारी किया जाएगा जब एक अधिकरण या प्राधिकरण ने अभी तक अपनी कार्यवाही समाप्त नहीं की है।एक बार जब एक निकाय द्वारा एक निर्णय दिया जाता है जो सरशियोरेराई अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, तो सरशियोरेराई जारी किया जा सकता है जब एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है।न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का पालन करने में विफलता से हो सकती है।यह वैध रूप से अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के बाद निकाय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकता है।यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है।जिस निकाय का निर्णय हमले के दायरे में आता है, वह एक संपार्श्विक तथ्य भी तय कर सकता है।

> अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य और अधिकार क्षेत्र ग्रहण करें।तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष सरशियोरेराई के एक रिट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से अछूते नहीं हैं।जहाँ तक तथ्य का निष्कर्ष है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, यह आम तौर पर रिट न्यायालय के लिए "सीमा से बाहर" मामला है।यही कारण है कि जिस निकाय के पास मामले को तय करने का अधिकार क्षेत्र है, उसके पास इसे सही या गलत तरीके से तय करने का अधिकार क्षेत्र है।यह केवल एक त्रुटि बन जाएगी और वह भी तथ्य की एक त्रुटि।हालाँकि, सकल यह राशि हो सकती है, यह कानून की त्रुटि के बराबर नहीं है।कानून की एक त्रुटि जो सरशियोरेराई के माध्यम से न्यायिक जांच के लिए असुरक्षित हो जाती है, वह भी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरि विष्णु कामथ *[*हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233] में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अदालत द्वारा तय किया जाने वाला मामला है।तथ्य का एक निष्कर्ष जो किसी भी साक्षय द्वारा समर्थित नहीं है, विकृत होगा और वास्तव में कानून की एक त्रुटि होगी जो रिट अदालत को हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगी।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि साक्षय का भारी भार निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है, तो यह निर्णय सरशियोरेराई अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी बना देगा।यह एक ऐसे निष्कर्ष के समान होगा जो सबूत द्वारा पूरी तरह से अनुचित है जो इस न्यायालय ने निर्धारित किया है *(*पैरी एंड कंपनी लिमिटेड देखें।P.C। पाल, आकाशवाणी *1970* एससी 1334:(1969) *2* एससीआर 976])।"

37. सरशियोरेराई की रिट जारी करने के लिए जिस कानून का निपटारा किया गया है, वह यह स्पष्ट करता है कि इस रिट का उद्देश्य अधिकार क्षेत्र की ज्यादतियों, कानून की त्रुटि जो स्पष्ट है, विकृत निष्कर्ष आदि को ठीक करना है।

38. तत्काल मामले में, पंजीयक के आदेश के खिलाफ आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।पंजीयक के आदेश के नागरिक परिणाम थे।अपीलीय प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना निश्चित रूप से आवश्यक था। इसलिए, निस्संदेह, आक्षेपित आदेश एक अर्ध-न्यायिक आदेश है और यह सरशियोरेराई की रिट जारी करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि त्रुटियां हों और यह भी कि यह रिट जारी करने के लिए एक मामला बनाता है।

39. इन सभी रिट याचिकाओं में, कुछ विवादों को छोड़कर तथ्यात्मक पहलुओं को लगभग स्वीकार कर लिया जाता है, जिन पर उचित स्थानों पर चर्चा की जाएगी।

40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है।

निहित किए गए मुद्दा

41. याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 18.04.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए अपनी प्रार्थना को प्रतिबंधित करता है और नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले की रिमांड के लिए जोर देना नहीं डालता है।

42. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से नं। 4, यह तर्क दिया जाता है कि रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी आदेश पारित करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था, इसलिए, आक्षेपित आदेश को अभिखंडित कर दिया जाए और नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया जाए और इसके अलावा मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है।

43. तत्काल याचिका में मांगी गई राहत इस प्रकार है:

> "ए। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पारित दिनांकित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना। 2 अपील सं. <आईडी1> "दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम पंजीयक, प्रभावी समितियाँ और अन्य" (अनुलग्नक संख्या। 1 याचिका के लिए) और आगे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक नामित करने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हो सकते हैं

याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता की अपील की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए समर्थ, निष्पक्ष और समर्थ अधिकारी।

बी. कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

44. वास्तव में, याचिका में, आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का एक आधार यह है कि अपीलीय प्राधिकरण एक ही समय में पंजीयक के साथ-साथ सहकारी समितियों के सचिव के रूप में भी काम कर रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उनसे अपील पर सुनवाई नहीं करने का अनुरोध किया था, लेकिन याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, अपील पर निर्णय लिया गया और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया।एक आधार में, यह भी कहा गया है कि आक्षेपित आदेश खराब है क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि प्रतिवादी सं. 4 राम गोपाल और मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता धोखाधड़ी की घोषणा पर आधारित थे कि पी. ओ. ए. लागू था, जबकि यह अब लागू नहीं था क्योंकि पी. ओ. ए. के लेखक की मृत्यु विलेख के निष्पादन से तीन साल पहले हो गई थी।

45. सदस्यता के संबंध में एक तथ्य का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। रिट 41200/02 नहीं वाली एक रिट याचिका। 1992 का शून्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया गया था (संक्षेप में, "इलाहाबाद याचिका"), जिसमें 27.11.1992 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"नोटिस जारी करें।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम एक अंतरिम परमादेश जारी करते हैं जिसमें निर्देश दिया जाता है कि

> प्रतिवादी को तीन महीने की अवधि के भीतर दून वैली ऑफिसर्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड देहरादून के रूप में जानी जाने वाली सोसायटी की प्रबंधन समितियों के गठन के लिए चुनाव आयोजित करना और पूरा करना और आगे सोसाइटी के लिए नए सदस्यों का नामांकन नहीं करना और उन्हें भूखंड आवंटित नहीं करना या उन पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति की सेवा की तारीख से एक महीने के भीतर जवाबी शपथ पत्र दायर करके कारण बताना।याचिकाकर्ता इसके साथ सेवा संलग्नक का शपथ पत्र दाखिल करेगा:X उक्त प्रतिवादीओं द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की स्वीकृति, जिसमें विफल रहने पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।"

46. 24.08.2002 पर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या की सदस्यता रद्द कर दी। 4 राम गोपाल, जिसे पंजीयक द्वारा 28.11.2002 दिनांकित एक आदेश द्वारा अलग कर दिया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा भूखंड को भी इस आधार पर फिर से शुरू किया गया था कि उपनियम 50 को देखते हुए निर्माण समय पर नहीं किया गया था।ऐसा 25.09.2002 पर किया गया था।इस बहाली को किसी भी मंच पर चुनौती नहीं दी गई थी।लेकिन जैसा कि कहा गया है, जब प्रतिवादी नहीं। 4 राम गोपाल ने निर्माण को बढ़ाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि, सबसे पहले, याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और दूसरा, कि मूल आवंटी D.P। नांगिया की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए किसी को भी अवैध रूप से भूखंड पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इन आपत्तियों को पंजीयक द्वारा दिनांकित 28.11.2002 आदेश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसकी अंत में आक्षेपित आदेश में पुष्टि गई थी।

47. 28.11.2002 दिनांकित आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी।संलग्नक 4 अपील का ज्ञापन है।आधार इस प्रकार हैं:-

(i) प्रतिवादी नं. 4 को इलाहाबाद याचिका में पारित दिनांक 1 के आदेश का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से सदस्य बनाया गया था।

(ii) प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल को याचिकाकर्ता द्वारा 24.08.2002 पर सदस्यता से हटा दिया गया था।

(iii) उत्तरदाता नं. 4 राम गोपाल ने सोसायटी के संदर्भ के बिना और सोसाइटी से पुष्टि किए बिना घर के निर्माण के लिए समय बढ़ाने की गलत मांग की कि क्या भूखंड प्रतिवादी सं। 4 राम गोपाल।

(iv) जब प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल ने अनधिकृत निर्माण शुरू किया, पुलिस को सूचित किया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई।

(v) प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल ने गुप्त रूप से और सोसायटी की अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने पक्ष में स्थानांतरण विलेख प्राप्त किया।

(vi) D.P द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा। मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में नांगिया। नरेश गुप्ता उस तारीख को अप्रभावी थे जब प्रतिवादी सं. के पक्ष में विलेख निष्पादित किया गया था। 4 राम गोपाल क्योंकि D.P। तीन साल पहले नांगिया की मृत्यु हो गई थी।

(vii) मूल पट्टा विलेख के खंड (4) के अनुसार सोसायटी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरण विलेख का निष्पादन नहीं किया जा सकता था।

(viii) प्रतिवादी नं. 4 सोसायटी के हस्तक्षेप के बिना गलत तरीके से मानचित्र को मंजूरी दे दी गई।

48. उपरोक्त पंजीयक द्वारा पारित दिनांकित 28.11.2002 आदेश को चुनौती देने के आधार थे।आक्षेपित आदेश में, अपीलीय प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ इस प्रकार टिप्पणी की:

(i) उत्तरदाता नं. 4 राम गोपाल ने मुख्तारनामा धारक मेजर (सेवानिवृत्त) से अपने नाम पर प्लॉट स्थानांतरित करवा लिया। नरेश गुप्ता; उन्होंने एम. डी. डी. ए. से स्वीकृत नक्शे भी प्राप्त किए और निर्माण शुरू किया, इसलिए, मूल्यवान अधिकार प्रतिवादी नं. 4 राम गोपाल और ऐसे मामले में भूखंड को फिर से शुरू करना उचित नहीं है क्योंकि यह प्रतिवादी सं. 4 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। 4 राम गोपाल।(पैरा 2)

(ii) मूल पट्टा विलेख में कोई शर्त नहीं है कि यदि समय के भीतर घर का निर्माण नहीं किया जाता है, तो सोसायटी द्वारा भूखंड को फिर से शुरू किया जाएगा।समाज द्वारा भूखंड को फिर से शुरू करना प्राकृतिक न्याय और मूल अधिकारों के सिद्धांत के खिलाफ है।(पैरा 3)

(iii) उप-कानून कानून नहीं हैं।इसलिए उपनियमों में दिए गए भूखंड को फिर से शुरू करना वैध नहीं है।(पैरा 4)

(iv) भले ही यह माना जाता है कि D.P। प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन से तीन साल पहले नांगिया की मृत्यु हो गई थी। 4, व्यथित पक्ष D.P का कानूनी प्रतिनिधि होता। नांगिया लेकिन उन्होंने प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में स्थानांतरण पर आपत्ति नहीं जताई। 4 राम गोपाल।भले ही सोसाइटी इसे एक धोखाधड़ी का कार्य मानती हो, सोसाइटी ने एक प्राथमिकी दर्ज की होगी या पंजीयक के साथ आपत्ति जताई होगी, जो नहीं की गई थी।(पैरा 6)

(v) इलाहाबाद याचिका में, दिनांकित 27.11.1992 आदेश याचिकाकर्ता द्वारा सेवा का एक शपथ पत्र दाखिल करने के बशर्ते था, जो दायर नहीं किया गया था।इसलिए 27.11.1992 दिनांकित आदेश का प्रभाव समाप्त हो गया था।इसे ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि सोसायटी में नए सदस्यों को शामिल करने पर कोई रोक थी।(पैरा 7)

(vi) सदस्यों को उपनियमों में शामिल करने की शर्त सहकारी समितियों के सिद्धांतों के खिलाफ है सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाना चाहिए।भूखंड को फिर से शुरू करने की शक्ति सामान्य निकाय के पास होनी चाहिए न कि प्रबंधन समिति के पास।(पैरा 10)

(vii) 55 से 57 तक के उपनियमों का उद्देश्य सोसायटी को बिक्री प्रतिफल का 1/10 th प्रदान करना है और यदि तत्काल मामले में सोसाइटी को प्रतिफल राशि का 1/10 th प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी सोसाइटी द्वारा इस राशि की मांग की जा सकती है।(पैरा 11 से 15)

(viii) एक बार समिति द्वारा भूखंड आवंटित किए जाने के बाद, सोसायटी को सदस्यों के मूल अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। (पैरा 16)

49. तथ्यों का उपरोक्त वर्णन यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी सं. की सदस्यता कैसे होगी। 4 को रद्द कर दिया गया था; सोसायटी द्वारा भूखंड को कैसे और क्यों फिर से शुरू किया गया था और याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं. 4 घर के निर्माण के लिए पंजीयक द्वारा और कैसे इसे पंजीयक द्वारा 28.11.2002 पर अस्वीकार कर दिया गया था।उपरोक्त वर्णन से यह भी पता चलता है कि वे कौन से आधार थे, जो याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 28.11.2002 आदेश के खिलाफ अपील में लिए गए थे।वास्तव में सभी उपलब्ध आधार याचिकाकर्ता द्वारा पंजीयक के दिनांकित 28.11.2002 आदेश को चुनौती देते हुए लिए गए थे।यह सदस्यता तक ही सीमित नहीं था, केवल फिर से शुरू हुआ, बल्कि इससे भी आगे चला गया।

50. ऊपर के रूप में यह भी कहा गया है कि शुरू में रिट याचिका का निर्णय केवल इस आधार पर किया गया था कि अधिनियम की खंड 128 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है।लेकिन विशेष अपील में, अदालत ने जो किया वह सभी मुद्दा को खोल देता है

चर्चा के लिए जब न्यायालय ने निर्देश दिया कि विरोधी दलीलें

"गुण" पर विचार किया जाना चाहिए।

51. वास्तव में, बहस के दौरान पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष हर पहलू का प्रचार किया गया है।इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि यह रिट याचिका अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की क्षमता या औचित्य निर्धारण तक सीमित नहीं है (याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों को देखते हुए कि संबंधित समय में अपीलीय प्राधिकरण पंजीयक के साथ-साथ सहकारी समितियों के सचिव का पद धारण कर रहा था)।18.04.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश को देखना होगा।इन याचिकाओं में बहस के दौरान उठाए गए सभी पहलुओं पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।ऐसा करने से, संक्षेप में, रिट याचिका का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा है।18.04.2015 दिनांकित आदेश आक्षेपित है।यह न्यायाधीश के हित में होगा कि एक बार और हमेशा के लिए पूर्ण और प्रभावी अधिनिर्णयन लिया जाए।तदनुसार, न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत बहस की सराहना करने के लिए आगे बढ़ता है।

52. इससे पहले कि न्यायालय अधिनियम की खंड 128 के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े ताकि इसकी प्रकृति का पता लगाया जा सके कि क्या यह अनिवार्य है या निर्देशिका, यह चर्चा करना उपयुक्त होगा कि अधिनियम क्यों है; अधिनियम क्या प्रदान करता है।

<u>सहयोगात्मक समाजों की अवधारणा</u>

53. जैसा कि नाम से पता चलता है, सहकारी समितियाँ निर्दिष्ट उद्देश्यों वाले व्यक्तियों का संगठन हैं।का इतिहास

इस देश में सहकारी आंदोलनों की जड़ें अतीत में हैं।राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ, सार्वजनिक जीवन में गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी तकनीकों को अपनाने का उद्देश्य है।नियुक्त प्राधिकारी केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि ऐसी समितियाँ इसके उपनियमों और इसके उद्देश्यों के अनुसार चलाई जाएं।उप-अधिनियम और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का इकरारनामा है (इस पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी), जो सोसायटी के उद्देश्य या उद्देश्यों के अनुरूप और अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए।

54. आंध्र प्रदेश सहकारी समितियों के मामले में बनाम.

A.P की सरकार। और अन्य[17.] माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस देश में सहकारी आंदोलन के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला था और पैरा 47 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:-

> "47. अपने स्वभाव से सहकारी आंदोलन स्वैच्छिक संघ का एक रूप है जहां व्यक्ति समानता, तर्क और सामान्य भलाई के सिद्धांतों पर धन के उत्पादन और वितरण में आपसी लाभ के लिए एकजुट होते हैं।इसलिए, एक सहकारी समिति के गठन का मूल उद्देश्य अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना है।एसोसिएशन के सदस्यों को केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने का अधिकार है जिन्हें वे भर्ती होने के योग्य मानते हैं और उन्हें उन लोगों को प्रवेश से इनकार करने का अधिकार है जिनके साथ वे जुड़ना नहीं चाहते हैं।समूह में अनुचित व्यक्तियों को जबरन शामिल करके संघ बनाने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।सहयोग करने का अधिकार अभिव्यंजक गतिविधियों में आनंद लेने के उद्देश्य से है। दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने के संवैधानिक अधिकार में संघ के सदस्यों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक लाभों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए सहयोगी संबंध शामिल हैं।वैधानिक हस्तक्षेपों द्वारा, राज्य को संघ के मौलिक चरित्र को बदलने या स्वयं समाज की संरचना को बदलने की अनुमति नहीं है।संघ की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण अतिक्रमण को सरकार के किसी भी हित के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।हालांकि, जब संघ सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हो जाता है, तो यह प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

[17] (2011) 9 एससीसी 286

> अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम।यदि संघ के पास किसी विशेष अधिनियम के तहत पंजीकृत होने का विकल्प/विकल्प है, यदि क्षेत्र में एक से अधिक अधिनियम काम कर रहे हैं, तो राज्य सोसायटी को उस अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जिसके लिए सोसाइटी ने आवेदन नहीं किया है।"

55. इसके अलावा, विपुलभाई एम. चौधरी बनाम गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और अन्य[18] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से सहकारी आंदोलन और सहकारी सिद्धांतों के पीछे के इतिहास का हवाला दिया।माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> "8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करने और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 43-बी को शामिल करने के अलावा, 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों पर एक नया भाग IX-B भी पेश किया।संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का संदर्भ लोकतांत्रिक आधार को मजबूत करने और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर देगा।इस प्रकार, भारत के संविधान में 97वें संशोधन के बाद सहकारी समितियों की अवधारणा पर संवैधानिक आकांक्षाओं को देखना होगा जो 12-1-2012 पर लागू हुआ था।
>
> "उद्देश्यों और कारणों का कथन
>
> 1. पिछले कुछ वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारी वृद्धि हासिल की है।हालाँकि, इसने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने में कमजोरियों को दिखाया है जिनके लिए इन संस्थानों को संगठित किया गया था।ऐसे उदाहरण हैं जहां चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और नामित पदाधिकारी या प्रशासक लंबे समय तक इन संस्थानों के प्रभारी रहे हैं।इससे सहकारी समितियों के प्रबंधन की अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेही कम हो जाती है।कई सहकारी संस्थानों में प्रबंधन में अपर्याप्त व्यावसायिकता के कारण खराब सेवाएं और कम उत्पादकता हुई है।सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने और समय पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की आवश्यकता है।इसलिए, इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए मौलिक सुधार शुरू करने की आवश्यकता है ताकि देश के आर्थिक विकास ठीक होना उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके और बड़े पैमाने पर सदस्यों और जनता के हितों की सेवा की जा सके।

---

[18] (2015) 8 एससीसी 1

उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और व्यावसायिक प्रबंधन।

2. 'सहकारी समितियाँ' प्रविष्टि में बताए गए एक विषय है।
संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के 32 और राज्य विधानमंडलों ने तदनुसार सहकारी समितियों पर कानून बनाए हैं।राज्य अधिनियमों के ढांचे के भीतर, सामाजिक और आर्थिक न्यायाधीश प्राप्त करने और विकास के फलों के समान वितरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास की परिकल्पना की गई थी।हालाँकि, यह अनुभव किया गया है कि सहकारी समितियों के काफी विस्तार के बावजूद, गुणात्मक रूप से उनका प्रदर्शन वांछित स्तर तक नहीं रहा है।राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अवसरों पर और राज्य सहकारी मंत्रियों के सम्मेलनों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। संविधान में संशोधन की सख्त आवश्यकता महसूस की गई है ताकि सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जा सके और उनके स्वायत्त संगठनात्मक ढांचे और उनके लोकतांत्रिक कामकाज को भी सुनिश्चित किया जा सके।

3.केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से काम करें।आवश्यक सुधारों को लाने के लिए, संविधान में एक नया भाग शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कामकाज जैसे सहकारी समितियों के काम करने के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने वाले कुछ प्रावधानों का प्रावधान किया जा सके।सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) में एक नया अनुच्छेद जोड़ने का भी प्रस्ताव है। संविधान में प्रस्तावित नया भाग, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को निम्नलिखित मामलों को निर्धारित करते हुए उचित कानून बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, अर्थात्:

(a) लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान;

(b) किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(c) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के संबंध में चुनाव की तारीख से पांच साल की एक निश्चित अवधि का प्रावधान;

(d) अधिकतम छह महीने की समय-सीमा प्रदान करना जिसके दौरान सहकारी समिति के निदेशक मंडल को अधिक्रमण या निलंबन के तहत रखा जा सकता है।

(e) स्वतंत्र व्यावसायिक लेखापरीक्षा प्रदान करना;

(f) सहकारी समितियों के सदस्यों को सूचना का अधिकार प्रदान करना;

(g) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों की गतिविधियों और खातों की आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना।

(h) प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान, जिसमें ऐसी श्रेणियों के सदस्य के रूप में व्यक्ति हैं;

(i) सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान और ऐसे अपराधों के संबंध में दंड।

4.यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रावधान न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे और कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निवारक का प्रावधान करेंगे।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।"

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 43-बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है:
"43-बी। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"

56. यह अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।अधिनियम की खंड 4 में प्रावधान है कि एक सोसायटी जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना है, ऐसी सोसाइटी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्यों के साथ स्थापित सोसाइटी द्वारा अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। खंड *7*, अन्य बातों के साथ साथ साथ, यह प्रावधान करती है कि उपनियम अधिनियम के प्रावधानों और उसमें बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं होने चाहिए। अधिनियम की खंड 9 के अनुसार, सहकारी समितियाँ निगमित निकाय हैं।अधिनियम की खंड *28*, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि सहकारी समिति का अंतिम अधिकार सामान्य बैठक में अपने सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होता है।की खंड 29

अधिनियम, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि सहकारी समितियों का प्रबंधन अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार गठित प्रबंधन समिति में निहित है, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो अधिनियम, नियमों या उपनियमों द्वारा प्रदत्त और अधिरोपित किए जा सकते हैं।अधिनियम की खंड 37 पंजीयक को अभिलेख आदि को जब्त करने के लिए आपातकालीन शक्तियां देती है। ऐसे मामलों में जब छेड़छाड़ की आशंका हो या सोसायटी के धन या संपत्ति का दुरुपयोग होने की संभावना हो, आदि। अधिनियम की खंड 29 (5) प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान करती है, जिसे पंजीयक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

57. उपरोक्त और अधिनियम के अन्य प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि मूल अवधारणा समूह गतिविधियों के शासन में सहकारी तकनीकें हैं।पंजीयक और अन्य अधिकारियों द्वारा से हस्तक्षेप इस हद तक सीमित है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सहकारी समितियां उन उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही हैं जिनके साथ उनका गठन किया गया था।इस संदर्भ में, अब अधिनियम की खंड 128 के प्रावधान की जांच की जाएगी।

<u>अधिनियम की खंड 128 का प्रावधान अनिवार्य या निदेशक है।</u>

58. तत्काल मामले में, पंजीयक का 28.11.2002 दिनांकित आदेश वास्तव में अधिनियम की खंड 128 के तहत पारित आदेश नहीं है। जैसा कि कहा गया है, यह आदेश घर के निर्माण के लिए समय बढ़ाने के खिलाफ याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर पारित किया गया था, जैसा कि पंजीयक द्वारा प्रतिवादी नं।4.बेशक, पंजीयक भी पास हो गए थे

28.11.2002 पर एक आदेश (पत्र सं. 691/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक <आई. डी. 1>) जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव। 4 को दरकिनार कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी शपथ पत्र के साथ दायर किया है, लेकिन यह भी पता नहीं चलता है कि ऐसा करते समय मामला पंजीयक द्वारा प्रबंधन समिति के प्रत्युतर के लिए भेजा गया था।

59. लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1101 और रिट याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1102, दिनांक 27.11.2002 के आदेश द्वारा (पत्र सं. 689/विधि/नीसा। दिनांकित 27.11.2002) और दिनांकित 28.11.2002 आदेश (पत्र सं. 692/विधि/नीसा। दिनांक 28.11.2002), क्रमशः 14.09.2002 और 24.08.2002 दिनांकित संकल्प को रद्द कर दिया गया था।यह अधिनियम की खंड 128 के तहत किया जाता है।

60. अधिनियम की खंड 128 के परंतुक ने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जब याचिका पर पहले 06.07.2018 पर निर्णय लिया गया था और तब न्यायालय ने कहा था कि उसमें उपयोग किया जाने वाला शब्द "होगा" अनिवार्य है।क्या यह अनिवार्य है?इसकी जांच होनी चाहिए।

61. अधिनियम की खंड 128 इस प्रकार है:-

> "128. किसी प्रभावी समिति के प्रस्ताव को निरस्त करने या कुछ मामलों में प्रभावी समिति के अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की पंजीयक की शक्तियाँ।- पंजीयक कर सकता है -
>
> (i) प्रबंधन समिति या किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को रद्द करना; या
>
> (ii) किसी अधिकारी या प्रभावी समिति द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द करना; यदि उसकी राय है कि प्रस्ताव या आदेश, जैसा भी मामला हो, समाज के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है, या इस अधिनियम, नियमों या समाज के उप-कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जहां -

> ऐसा प्रत्येक संकल्प या आदेश अमान्य और प्रभावी हो जाएगा और सोसायटी के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा।
>
> बशर्ते कि, पंजीयक, कोई आदेश देने से पहले, प्रबंधन समिति, सामान्य निकाय या सहकारी समिति के अधिकारी से ऐसी अवधि के भीतर, जो वह निर्धारित करे, लेकिन जो पंद्रह दिनों से कम न हो, प्रस्ताव पर या आदेश पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा और यदि वह उचित समझता है तो उस अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या आदेश के संचालन पर रोक लगा सकता है।"
>
> (जोर दिया गया)

62. विशेष अपील में जब 06.07.2018 दिनांकित आदेश पर हमला किया गया था, तो विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, जो "होगा" शब्द की अनिवार्य या निर्देशिका के रूप में व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।व्याख्या का नियम बहुत संतुलित और सरल है कि एक शब्द को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसके संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है।संदर्भ से बाहर पढ़ने की अनुमति नहीं है।व्याख्या के विभिन्न नियम, वास्तव में, उस स्थिति में लागू किए जाते हैं जहां कोई अस्पष्टता होती है; अधिनियम बनाने में विधानमंडल के इरादे का पता लगाने के लिए।

63. क्या "होगा" शब्द, जहाँ भी और जो भी संदर्भ में उपयोग किया जाता है, उसे अनिवार्य के रूप में लिया जाना चाहिए या इसे निर्देशिका के रूप में भी माना जा सकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत क्या हैं?

64. U.P की स्थिति के मामले में। और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय [19]. माननीय उच्चतम न्यायालय ने "होगा" शब्द की व्याख्या पर चर्चा की और इस विषय पर विभिन्न निर्णयों को संदर्भित किया और जैसा कि नीचे कहा गया है:-

> "29. व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:जब कोई अधिनियम "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथमदृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय सावधानीपूर्वक विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है।

---

[19] आकाशवाणी 1961 एससी 751

अधिनियम के पूरे दायरे में भाग लेना विधानमंडल के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, अधिनियम की प्रकृति और रूपरेखा और इसे एक या दूसरे तरीके से समझने से होने वाले परिणामों पर विचार कर सकता है, अन्य प्रावधानों के प्रभाव से बचा जा सकता है, जिसमें सम्बंधित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात्, अधिनियम प्रावधानों का पालन न करने की आकस्मिकता, इस तथ्य का प्रावधान करता है कि प्रावधानों का पालन न करने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या नहीं, इससे होने वाले गंभीर या तुच्छ परिणाम, और सर्वोपरि बढ़कर, क्या अधिनियम का उद्देश्य पराजित या आगे बढ़ाया जाएगा।"
(जोर दिया गया)

65. राजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड के मामले में।

नगरपालिका बोर्ड, रामपुर[20] माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "होगा" शब्द की व्याख्या के संबंध में समान सिद्धांतों को अपनाया गया है और जिन विचारों को जोड़ा गया है उनमें से एक है "व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय जिसके परिणामस्वरूप क्या प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है, उसी विषय से संबंधित अन्य प्रावधानों के लिए विशेष प्रावधान का संबंध और प्रावधान की भाषा सहित किसी विशेष मामले के तथ्यों पर उत्पन्न होने वाले अन्य विचार, इन सभी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या कोई विशेष प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका है।"

66. बलवंत सिंह और अन्य बनाम आनंद कुमार शर्मा और अन्य के मामले में [21]माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

---

[20] आकाशवाणी 1965 एससी 895
[21] (2003) 3 एस. सी. सी. 433

"7. फिर भी इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा एक निर्दिष्ट समय के भीतर कोई काम करने की आवश्यकता होती है, तो वह सामान्य रूप से अनिवार्य होगा, लेकिन जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को एक समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे निर्देशिका के रूप में तब तक माना जाएगा जब तक कि उसके परिणाम निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं।एस. टी. ए. के सांविधिक निर्माण में, 3 रा संस्करण, खंड। 3 पी पर। 107, यह इंगित किया गया है कि निजी व्यक्तियों के लिए एक वैधानिक निर्देश को आम तौर पर अनिवार्य माना जाना चाहिए और यह कि नियम सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में प्राप्त होने वाले नियम के बिल्कुल विपरीत है।फिर से, पी।109, अक्सर यह प्रश्न इंगित किया जाता है कि क्या किसी वैधानिक प्रावधान के लिए एक अनिवार्य या निर्देशिका निर्माण दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण अधिनियम में ही परिणाम की एक अभिव्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो प्रावधान का पालन नहीं करेगा।पी.111 यह निम्नलिखित रूप में कहा गया है:

> "ऊपर उल्लिखित नियम के एक परिणाम के रूप में, इस तथ्य को कि अधिनियम में गैर-अनुपालन के कोई परिणाम नहीं बताए गए हैं, एक निर्देशिका निर्माण की ओर बढ़ने वाले कारक के रूप में माना गया है। लेकिन यह केवल एक तत्व है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, और किसी भी तरह से निर्णायक नहीं है।"

67. इसके अलावा, शेख सलीम हाजी अब्दुल खैमसाब बनाम कुमार और अन्य के मामले में [22] माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून में उपयोग किए जाने पर "होगा" शब्द की व्याख्या की और जैसा कि नीचे कहा गया है:

> "14. प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, एक बाधा नहीं बल्कि न्यायाधीश के लिए एक सहायता है।प्रक्रियात्मक प्रिस्क्रिप्शन नौकरानी हैं न कि मालकिन, एक स्नेहक, न्यायाधीश के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं हैं।
>
> 15. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि आदेश 8 के नियम 1 से जुड़े परंतुक के तहत अदालत की शक्ति "नब्बे दिनों के बाद नहीं होगी" शब्दों से सीमित है, लेकिन समय का विस्तार न होने से होने वाले परिणामों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें आवश्यक निहितार्थ से पढ़ा जा सकता है।केवल इसलिए कि कानून का एक प्रावधान अनिवार्य चरित्र को दर्शाने वाली नकारात्मक भाषा में है, यह अपवादों के बिना नहीं है।जब न्यायालयों से प्रावधान की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वे उस पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था, इसे निर्देशिका मान सकते हैं, हालांकि इसे नकारात्मक रूप में लिखा गया है।"

68. उपरोक्त मामले के कानूनों और इस विषय पर अन्य विभिन्न मामले के कानूनों में निर्धारित अनुपात से यह स्पष्ट होता है कि मार्गदर्शक सिद्धांत यह होगा कि शब्द का उपयोग करने में विधानमंडल का क्या इरादा है।यह मूल परीक्षा है।इसके बाद

[22] (2006) 1 एससीसी 46

परिणाम; इसका प्रभाव या इसकी मूल या प्रक्रियात्मक प्रकृति या क्या यह एक निजी व्यक्ति या एक सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा किया गया कार्य है; ये सभी कारक हैं जो शब्द की प्रकृति को निर्धारण करते हैं कि क्या यह अनिवार्य है या निर्देशिका है।

69. अधिनियम की योजना की चर्चा पिछले पैराग्राफ में की गई है।अंतिम प्राधिकरण सोसायटी का सामान्य निकाय है।कुछ कार्य प्रबंधन समिति को सौंपे जाते हैं।पंजीयक और अन्य अधिकारियों को केवल सोसायटी की गतिविधियों की निगरानी करनी होती है।वे केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब यह पाया जाए या यह मानने के कारण हों कि सोसायटी ठीक से काम नहीं कर रही है।उसके संदर्भ में, यदि अधिनियम की खंड 128 को देखा जाए, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि "शब्द" को निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य नहीं माना जा सकता है:

(i) खंड 128 सहकारी समिति के प्रस्ताव को निरस्त करने या सहकारी समिति के किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द करने के लिए पंजीयक की शक्ति है।अब परंतुक की आवश्यकता यह है कि निर्णय लेने से पहले, पंजीयक मामले को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्विचार के लिए भेजेगा, लेकिन यह खंड परिणाम प्रदान नहीं करती है।15 दिनों की समाप्ति के बाद भी, सोसाइटी या उसका अधिकारी प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं करता है या पंजीयक के निर्देश में भाग नहीं लेता है या पुनर्विचार के बाद लिए गए अपने निर्णय को पंजीयक को सूचित नहीं करता है, तो क्या होगा।अधिनियम की खंड 128 के तहत परिणाम नहीं दिए गए हैं। इन सब में

अंततः, पंजीयक को मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है।इसका मतलब है कि पुनर्विचार के लिए 15 दिनों के समय का ज्यादा असर नहीं है।यह केवल निर्देशिका है।परिणामों को परिभाषित न करने में विधानमंडल की मंशा इसका समर्थन करती है।

70. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम की खंड 128 का प्रावधान, जहां तक वह पंजीयक को प्रबंधन समिति आदि की आवश्यकता के लिए बाध्य करता है। पुनर्विचार करने के लिए, संकल्प निर्देशिका है।यह अनिवार्य नहीं है।

<u>बाय-लॉज़ बनाम लॉज़</u>

71. प्रतिवादी नं. की ओर से एक तर्क दिया गया है। 4 कि उपनियम कानून नहीं हैं।वे अनुबंध अधिनियम या T.P के तहत प्रदान किए गए वैधानिक प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक्ट करें। प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान वकील। 4 ने इस बिंदु पर बी. अंजनेयुलु (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर निर्भरता रखी है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि उपनियम कानून नहीं हैं।इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उपनियम कानून नहीं हैं।वे अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं।जैसा कि कहा गया है, अधिनियम की खंड 7 में प्रावधान है कि एक सहकारी समिति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि पंजीयक संतुष्ट न हो कि प्रस्तावित उपनियम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। सहकारी समितियाँ मूल रूप से कुछ सामूहिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का संगठन हैं।वे सोसायटी को चलाने के तरीके के बारे में उपनियमों से सहमत हैं।यह और कुछ नहीं बल्कि एक

इकरारनामा जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य खुद को बांधता है।वे निश्चित रूप से कानून के खिलाफ नहीं हो सकते हैं।

72. सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में [23]माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपनियमों की अवधारणा पर चर्चा करते हुए कहा कि "अधिनियम द्वारा जिन उपनियमों पर विचार किया गया है, वे केवल वे हो सकते हैं जो किसी समाज के आंतरिक प्रबंधन, व्यवसाय या प्रशासन को नियंत्रित करते हैं।वे उनसे प्रभावित व्यक्तियों के बीच बाध्यकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अधिनियम का बल नहीं है।सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले उपनियमों के संबंध में, उपनियम सोसायटी और कर्मचारियों के बीच ठीक उसी तरह बाध्यकारी होंगे जैसे पार्टियों के बीच अनुबंध द्वारा निर्धारित सेवा की शर्तें।वास्तव में, सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले ऐसे उपनियम बनाए जाने और किसी भी व्यक्ति के सोसायटी के रोजगार में प्रवेश करने के बाद, सेवा की उन शर्तों को सेवा में प्रवेश करते समय कर्मचारी द्वारा स्वीकार की गई शर्तों के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार वह विशेष रूप से सेवा अनुबंध का हिस्सा बनने वाली सेवा की शर्तों के रूप में बाध्य होगा।"

73. U.P की स्थिति के मामले में। और एक अन्य v. C.O.D। छेओकी कर्मचारी सहकारी समिति और अन्य [24] माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक समाज के सदस्य की स्थिति पर बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा की और कहा कि-

[23] (1969) 2 एससीसी 43
[24] (1997) 3 एससीसी 681

> "16. इस प्रकार, यह व्यवस्थित कानून है कि किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत सहकारी समिति का सदस्य बनने का मौलिक अधिकार नहीं है।उसका अधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।इसलिए, समाज का सदस्य बनने या बने रहने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने पर और सोसायटी का सदस्य होने के लिए और प्रवेश पर, वह सदस्य बन जाता है।उसका सोसायटी का सदस्य होना समय-समय पर लागू होने वाले अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के संचालन के बशर्ते है।समाज के एक सदस्य को समाज के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और यह वह समाज है जो निगमित समुच्चय के रूप में प्रतिनिधित्व करने का हकदार है।कोई भी व्यक्तिगत सदस्य अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों की संवैधानिकता पर चुनौती करने का हकदार नहीं है और इसके संचालन के बशर्ते है।धारा स्रोत से अधिक ऊपर नहीं उठ सकती है।"
>
> (जोर दिया गया)

74. सिद्धेश्वर सहकारी सखार कर्मना एल. डी. के मामले में। V. आयकर आयुक्त और अन्य [25.] इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उप-कानूनों के दायरे पर चर्चा की ताकि यह माना जा सके कि यह एक सोसायटी के सदस्यों के बीच किया गया इकरारनामा है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> "48. एक बात और ध्यान देने योग्य है।जमा की अनिवार्य प्रकृति पर राजस्व और उच्च न्यायालय ने भी जोर दिया है कि यह जमा के विचार के लिए अप्रिय है।यह बताया गया है कि सदस्य के पास पूर्व निर्धारित शर्तों पर कटौती के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और कानून में जमा करने का अनुबंध नहीं हो सकता था।हालाँकि, यह दलील हमें आकर्षित नहीं करता है।एक व्यक्ति एक सहकारी समिति का सदस्य बन कर, स्वयंसेवकों को समिति के उपनियमों का पालन करना के लिए, जिसका वास्तविक उद्देश्य सदस्यों को सहायता प्रदान करने सहित समिति के आंतरिक प्रबंधन का प्रावधान करना है। इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि सहकारी समिति के उपनियम उसके प्रबंधन निकाय और उसके घटकों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली समिति के बीच एक अनुबंध का गठन करते हैं।इस कानूनी स्थिति को हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी बनाम सोसायटी के पंजीयक [(2000) *1* एस. सी. सी. 566] *(*पैराग्राफ *28* के माध्यम से) में मान्यता दी गई है।कूप में।सेंट्रल बैंक लिमिटेड बनामएडल्ट।औद्योगिक अधिकरण [(1969) *2* एस. सी. सी. 43] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सहकारी समिति अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के आधार पर बनाए गए सोसायटी के उप-नियम एक कंपनी संस्था के अंतर्नियम के बराबर थे, जो अच्छी तरह से स्थापित है, कंपनी और उसके सदस्यों के बीच और सदस्यों के बीच एक अनुबंध स्थापित करता है (नरेश चंद्र सान्याल बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन अपने में से पैराग्राफ 14 के अनुसार। लिमिटेड *[(1971) 1* एस. सी. सी. 50])।इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि अनुबंध को कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप और अपने आप में बशर्ते किया जाना है, अनुबंध में सहमति वाले तत्व पर निहित नहीं है।"कानून का दबाव जबरदस्ती नहीं है" और इस तरह की मजबूरी के बावजूद, "कानून की नजर में, इकरारनामा स्वतंत्र रूप से किया जाता है",

---

[25] (2004) 12 एससीसी 1

आंध्र शुगर लिमिटेड बनाम में इंगित किया गया है ।*A.P* की स्थिति । [ए. आई. आर 1968 एस. सी. 599:(1968) 1 एससीआर 705]।"

75. प्रत्येक इकरारनामा अधिकांश समय किसी व्यक्ति की गतिविधियों के क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है ।इकरारनामा वैध या गैरकानूनी हो सकता है ।समाज के उद्देश्य भी परिभाषित किए जाते हैं ।किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की जांच समाज के उद्देश्य के साथ-साथ उपनियमों की तुलना में की जानी चाहिए ।निस्संदेह उप-कानून क़ानून पर हावी नहीं हो सकते हैं; वे देश के किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर यह याद रखना होगा कि उप-कानून समाज के सदस्यों के बीच इकरारनामा के अलावा और कुछ नहीं हैं ।उनका परीक्षण अनुबंध अधिनियम के तहत दिए गए इकरारनामा के अनुसार होना चाहिए । कौन से इकरारनामा अमान्य हैं और कौन से अमान्य हैं, यह अनुबंध अधिनियम में दिया गया है । उपनियमों का परीक्षण केवल उस सीमा तक किया जा सकता है ।यदि ऐसा नहीं है, तो शायद एक सहकारी समिति बनाने के उद्देश्य बहुत जल्द गायब हो सकते हैं ।

76. इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है ।मान लीजिए कि एक सहकारी समिति का गठन अपने सदस्यों के आवासीय उद्देश्य के लिए घरों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, तो समिति द्वारा भूमि खरीदी जाती है और एक समय अवधि के भीतर निर्माण करने के लिए अपने सदस्य को पट्टे पर आवंटित किया जाता है, जिसमें निर्धारित किया जाता है कि यदि इस तरह का निर्माण नहीं किया जाता है, तो परिणाम दिए गए समय के भीतर होंगे ।अब अगर यह माना जाए कि एक बार आवंटित होने के बाद सदस्य संपत्ति का उपयोग वैसे ही कर सकता है जैसे वह महसूस करता है और सदस्यों में से एक किसी व्यावसायिक प्रकार के परिसर, खुले जिम, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्विमिंग पूल, ऐसे समाज में होटल बनाना शुरू कर देता है, तो क्या वह ऐसा कर सकता है ।यदि इसकी अनुमति है, तो एक सहकारी समिति बनाने का मूल उद्देश्य

समाज पराजित हो जाता है।यदि प्रत्येक सदस्य उसे आवंटित भूखंड का उपयोग अपने तरीके से करना शुरू कर देता है, कुछ होटलों के लिए, कुछ स्विमिंग पूल के लिए, कुछ खुले जिम के लिए, सोसाइटी के किसी भी नियंत्रण के बिना, शायद इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।बेशक यह भी उतना ही सच है कि उपनियम अनुबंध अधिनियम के तहत दिए गए इकरारनामा के अवयवों के अनुरूप होने चाहिए। वस्तुओं को कानून द्वारा या कानून के किसी भी प्रावधान को विफल करने या धोखाधड़ी या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने आदि के लिए निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

77. किसी इकरारनामा का एक और उदाहरण हो सकता है।

मान लीजिए कि ए अपनी संपत्ति बी को बेचने के लिए सहमत हो जाता है और बाद में बी को इस आधार पर संपत्ति बेचने से इनकार कर देता है कि वह अपनी संपत्ति किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है और क्योंकि उसे सी से अधिक कीमत मिल रही है, वह इसे सी को बेच देगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ए ने अपनी संपत्ति बी को बेचने के लिए खुद को बाध्य किया है। यह उपनियमों की स्थिति है।इसलिए, निस्संदेह उपनियम कानून नहीं हैं, लेकिन वे अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति के रूप में जाने जाने वाले संघ बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा सहमत शर्तें हैं। उपनियम स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं।उपनियम निश्चित रूप से भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकते हैं क्योंकि हस्तांतरण, उपयोग, सब कुछ सहकारी समिति के उपनियमों द्वारा उद्देश्यों के साथ नियंत्रित किया जाता है। उपनियम यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि किसे सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इसे किस तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।

<u>प्रतिवादी सं. 4.</u>

78. यह एक स्वीकृत मामला है कि 03.11.1993 प्रतिवादी नं. 4 को तत्कालीन प्रशासक द्वारा सोसायटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।याचिकाकर्ता की इस पर दो आपत्तियाँ हैं:

(i) सोसायटी के आम निकाय ने 18.7.1993 पर आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें नए सदस्यों के नामांकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तब तक भूखंडों के आवंटन को रोक दिया गया है, जब तक कि आम निकाय के अगले निर्णय और प्रतिवादी संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऐसे संकल्प की अवज्ञा की गई थी; और

(ii) इलाहाबाद याचिका में, 27.11.1992 पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोसायटी में किसी भी नए सदस्य को प्रवेश नहीं देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

79. पैरा 3 (बी. बी.) में, याचिकाकर्ता द्वारा सोसायटी के सामान्य निकाय के दिनांकित <आई. डी. 1> प्रस्ताव का विवरण दिया गया है।अपने जवाबी शपथ पत्र में, प्रतिवादी नं। 4, इसके उत्तर में कहा गया है कि दिनांक 1 का प्रस्ताव रिट याचिका के साथ दायर नहीं किया गया था और आगे कहा गया है कि "सोसाइटी के सदस्य के नामांकन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एजीएम द्वारा लिया गया कोई भी प्रशासनिक निर्णय आत्यन्तिक रूप अनावश्यक है और यह अधिकार क्षेत्र के बिना है जो उपनियमों के अनुरूप नहीं है और किसी व्यक्ति के अधिकार के अनुरूप नहीं है, जो सोसाइटी के सदस्य के रूप में होने के योग्य है।"

80. प्रतिवादी नं। 4 ने अपने जवाबी शपथ पत्र में कहा है कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद याचिका में एक याचिका दायर करने की आवश्यकता थी।

सेवा का शपथ पत्र जिसके साथ आदेश की स्वीकृति होती है, जिसमें विफल रहने पर आदेश का प्रभावी बंद कर दिया जाना था।यह कहा गया है कि इलाहाबाद याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा सेवा का ऐसा शपथ पत्र कभी दायर नहीं किया गया था।इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्राप्त एक प्रश्न उत्तर प्रपत्र जवाबी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

81. प्रतिवादी एन. ओ. एस.। 1 से 3 ने अपने जवाबी शपथ पत्र में, पैरा 21 में, सदस्यता के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा।इस पैराग्राफ में जो कहा गया है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति को उचित विलेख द्वारा से संपत्ति मिली है, तो इसे सोसायटी के उपनियमों के प्रावधान के तहत फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है।

82. हालाँकि अनुच्छेद 3 (बी. बी.) में रिट याचिका में <आई. डी. 1> दिनांकित प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था और यह दर्ज किया गया है कि यह प्रत्युतर 2-ए है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युतर आर. ए.-1 के रूप में जवाबी शपथ पत्र के साथ दायर किया गया था।लेकिन, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार में ही रिट याचिका में कहा है कि सामान्य निकाय ने अपने संकल्प दिनांक 18.07.1993 द्वारा संकल्प लिया था कि अगले आदेश तक नए सदस्यों का नामांकन नहीं किया जाए और उन्हें भूखंड आवंटित नहीं किए जाएं।यह कानून के खिलाफ कैसे है?अधिनियम की खंड 28 सहकारी समितियों के सामान्य निकाय को अपने मामले से निपटने की पूरी शक्ति देती है।आम सभा ने संकल्प लिया कि किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

83. यह भी सच है कि प्रशासक हालांकि नए सदस्यों को शामिल कर सकता है। लेकिन, यदि प्रशासक ने सामान्य निकाय के दिनांकित 18.07.1993 के प्रस्ताव को रद्द कर दिया होता, तो इसकी ओर से कोई कानाफूसी नहीं होती।

राज्य।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकरण, पंजीयक सभी इस रिट याचिका में पक्षकार हैं जिनकी ओर से जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है।उन्होंने कुछ नहीं कहा है।यह रिकॉर्ड की बात थी, वे इसे सत्यापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।इसका मतलब है कि सोसायटी के सामान्य निकाय का दिनांक 18.07.1993 का एक प्रस्ताव था जिसमें सोसाइटी के नए सदस्यों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।प्रशासक ने इसका पालन नहीं किया।क्यों?प्रशासक के लिए प्रतिवादी संख्या को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। 4 एक सदस्य के रूप में, वह भी, सामान्य निकाय के प्रस्ताव को याद या रद्द किए बिना, जो अन्यथा अपने कामकाज में सोसायटी का सर्वोच्च निकाय है।यह समावेशन को कानून के खिलाफ और अस्वीकार्य बनाता है।केवल इस गणना पर, प्रतिवादी सं. 4 03.11.1993 पर सोसायटी के सदस्य के रूप में अनुमति नहीं थी।यह क़ानून के खिलाफ था; उपनियमों के खिलाफ।

84. एक अन्य प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद याचिका में पारित दिनांक 1 के आदेश का प्रभाव है।यह सच है कि इलाहाबाद याचिका में नए सदस्यों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाते हुए और अन्य निर्देश देते हुए, न्यायालय ने उसमें याचिकाकर्ता से सेवा का एक शपथ पत्र दायर करने की अपेक्षा की थी, जिसमें विफल रहने पर यह आदेश दिया गया था कि आदेश का प्रभावी बंद कर दिया जाएगा।सेवाक शपथ पत्रपत्र दाखिल नहि कयल गेल छल, ई प्रतिवादी सं।4.

85. जैसा कि कहा गया है, 28.11.2002 पर (जैसा कि पत्र सं. 691/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक 28 नवंबर, 2002), पंजीयक ने संकल्प सं. याचिकाकर्ता के 4 सदस्य जिनके द्वारा

प्रतिवादी की सं. 4 को रद्द कर दिया गया।यह आदेश याचिकाकर्ता के जवाबी शपथ पत्र का प्रत्युतर 5 है।पृष्ठ 2 के पैरा 2 में, इस आदेश के निचले पैराग्राफ में, पंजीयक ने दर्ज किया है कि समिति के सचिव ने इलाहाबाद याचिका में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया था और अदालत को 27.11.1992 पर दिए गए निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युतर शपथ पत्र में कहा है कि वास्तव में, सेवा का हलफनामा तत्कालीन याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन उनके वकील की मृत्यु के कारण, इसे समय पर दायर नहीं किया जा सका।

86. अब दो मुद्दा हैं।इसके एक आदेश दिनांक 28.11.2002 में (जैसा कि पत्र सं. 691/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक 28 नवंबर, 2002), पंजीयक ने दर्ज किया है कि इलाहाबाद याचिका में, सोसायटी के सचिव ने अदालत को आश्वासन देते हुए एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया था कि <आईडी1> पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा था।इसका मतलब है कि सेवा प्रशासक या सोसायटी के सचिव पर की गई थी।अब अगर इलाहाबाद याचिका में इसका सबूत दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है?रूप और पदार्थ दो चीजें हैं। किसी काम को पूरा करना और उसका प्रमाण प्राप्त करना दो अलग-अलग चीजें हैं।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.11.1992 के आदेश का वास्तव में पालन किया गया था क्योंकि जैसा कि कहा गया है, सोसायटी के सचिव द्वारा इलाहाबाद याचिका में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया था जो दर्शाता है कि न्यायालय के दिनांकित 27.11.1992 के निर्देश का पालन किया जा रहा था।अब केवल इसलिए कि कोई प्रमाण दाखिल नहीं किया गया था, यह प्रशासक को सदस्य को शामिल करने का अधिकार नहीं देता है।

87. यदि सोसायटी की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि कोई नया सदस्य शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि सेवा पर्याप्त थी।ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रमाण न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया जा सका।वास्तव में, इलाहाबाद याचिका पर बाद में निर्णय लिया गया था।इन तथ्यों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था कि सेवा का शपथ पत्र तैयार किया गया था, लेकिन वकील की मृत्यु के कारण शपथ पत्र दायर नहीं किया जा सका या वास्तव में, प्रशासक और सोसायटी के सचिव को आदेश दिया गया था।यदि इस तथ्य को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता, तो शायद नोटिस दिए बिना आदेश लागू रहता।लेकिन, इस न्यायालय का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा का शपथ पत्र दायर नहीं किए जाने के बावजूद, 27.11.1992 दिनांकित आदेश 03.11.1993 पर लागू था क्योंकि सोसायटी के सचिव ने स्वयं इलाहाबाद याचिका में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया था जिसमें अदालत को आश्वासन दिया गया था कि 27.11.1992 दिनांकित निर्देशों का पालन किया जा रहा था।

88. इस न्यायालय का मानना है कि 03.11.1993 पर, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लागू था, जिसके द्वारा नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई थी।प्रतिवादी नं. 4 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए शामिल किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी सं. इस मामले में 4 भी अवैध है।यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सोसायटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

89. यह भी तर्क दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य हो सकता है और उपनियम इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं।अधिनियम की खंड 17 का संदर्भ दिया गया है, जो पात्रता मानदंड प्रदान करती है

किसी सोसायटी का सदस्य बनना।यह सच है कि अधिनियम की खंड 17 उन व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करती है, जो एक सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सहकारी समिति के अपने उपनियम होते हैं।यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारी समितियाँ और कुछ नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है।कोई भी व्यक्ति समाज का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता है।उसे उपनियमों की शर्तों को पूरा करना होता है।इसलिए इस आधार पर दिए गए बहस का कोई बल नहीं है।

90. एक तर्क यह भी दिया गया है कि एक सदस्य को केवल आम सभा की बैठक से निष्कासित किया जा सकता है न कि प्रबंधन समिति द्वारा।इस तर्क का कोई बल नहीं है।

91. अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 56 में यह प्रावधान है कि सहकारी समिति से सदस्य के रूप में किसे हटाया जा सकता है।नियम 57 और 58 प्रक्रिया प्रदान करते हैं और यह प्रबंधन समिति है जो एक सदस्य को नोटिस देती है जिसे सोसायटी से हटाने का प्रस्ताव है। 24.8.2002 पर बिंदु संख्या पर संकल्प द्वारा। 4, प्रतिवादी की सदस्यता सं। 4 को हटा दिया गया।यह प्रबंधन समिति द्वारा उपनियमों के तहत किया जा सकता है और इस मामले में यही किया जाता है।

92. चालू चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी नहीं। 4 गलत तरीके से, अवैध रूप से किया गया था और इलाहाबाद याचिका में पारित 27.11.1992 के आदेश की अवहेलना करते हुए 03.11.1993 पर सोसायटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।प्रतिवादी सं। 4 एक सदस्य के रूप में सोसायटी के सामान्य निकाय के दिनांक 18.07.1993 के प्रस्ताव की भी अवहेलना की गई थी।वह सही थे।

24.08.2002 पर प्रबंधन समिति द्वारा बिंदु संख्या पर एक प्रस्ताव द्वारा सोसायटी की सदस्यता से हटा दिया गया।4.

<u>मुख्तारनामा और अधिकार सं। 4.</u>

93. प्रतिवादी की ओर से सं। इस मुद्दे पर 4 अलग-अलग बहस दिए गए हैं।याचिकाकर्ता की ओर से, सीमित तर्क यह है कि D.P की मृत्यु के बाद। 13.05.1998 पर नांगिया, उनके द्वारा निष्पादित पी. ओ. ए. प्रभावी नहीं रहा और प्रतिवादी सं. के पक्ष में दिनांकित 23.07.2001 हस्तांतरण विलेख। 4 राम गोपाल अमान्य है क्योंकि इसे मेजर (सेवानिवृत्त) द्वारा निष्पादित किया गया है। नरेश गुप्ता बिना किसी अधिकार के, सोसायटी की पूर्व अनुमति के बिना, जो उपनियमों के अनुसार अनिवार्य है।

94. यह तर्क दिया जाता है कि मुख्तारनामा निष्पादित किया गया था D.P। मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में नांगिया। नरेश गुप्ता 07.01.1991 पर विचार के लिए, इसलिए, मेजर (सेवानिवृत्त)। नरेश गुप्ता का संपत्ति में हित है और निष्पादक की मृत्यु के बाद अनुबंध अधिनियम की खंड 202 को देखते हुए पी. ओ. ए. समाप्त नहीं होता है।

95. अनुबंध अधिनियम की खंड 202 इस प्रकार है:

> "202. अभिकरण की समाप्ति, जहाँ अभिकर्ता की विषय-वस्तु में रुचि हो।- जहाँ अभिकर्ता का स्वयं उस संपत्ति में हित है जो अभिकरण का विषय है, अभिकरण को, एक स्पष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में में, ऐसे हित के पक्षपातपूर्ण के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

96. पी. ओ. ए. प्रतिवादी सं. द्वारा दायर किया गया है। 4 स्वयं अपने शपथ पत्र दिनांक 17.06.2018 के साथ।यह कहीं भी उस D.P को दर्ज नहीं करता है।

नांगिया ने मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में पी. ओ. ए. निष्पादित किया। विचार के लिए नरेश गुप्ता।किसी भी "विचार" का कोई उल्लेख नहीं है।यह केवल सदस्य की ओर से कार्य करने का अधिकार है।इस पी. ओ. ए. का पैरा 9 इस प्रकार है:

> "9. जमीन के उक्त भूखंड की बिक्री के संबंध में दून वैली ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, वसंत विहार, मौज़ा कांवाली, देहरादून के अधिकारियों से अनुमति लेना।"

97. दस्तावेज़ को जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए।प्रतिवादी नं। 4, जो इस पी. ओ. ए. पर निर्भर है, उसे इस पी. ओ. ए. में मौखिक रूप से कुछ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पी. ओ. ए. को पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए, यह कहना कि मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता की इस भूखंड में कोई रुचि नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है।

<u>D.P की मृत्यु का प्रभाव। 13.05.1998 पर नांगिया</u>

98. D.P। नांगिया समाज की सदस्य थीं।उन्होंने खुद को उपनियमों से बांध लिया था।उप-कानून 55 के तहत प्रदान किए गए हस्तांतरण पर प्रतिबंध स्वयं लगाया गया प्रतिबंध है।जैसा कि कहा गया है, यह समाज के सदस्यों के बीच एक इकरारनामा है।यह कानून के खिलाफ नहीं है।यह इकरारनामा अमान्य नहीं है, इसलिए उपनियम 55 के तहत हस्तांतरण पर प्रतिबंध विधिसम्मत है।तत्काल मामले में, मेजर (सेवानिवृत्त) द्वारा स्थानांतरण। नरेश गुप्ता बिना किसी वैध प्रवर्तनीय अधिकार के थे और उपनियम 55 के प्रावधानों के खिलाफ थे, इसलिए, यह प्रतिवादी सं. 4 प्लॉट पर।

99. यह भी तर्क दिया गया है कि मुख्तारनामा में बिक्री का एक तत्व है।इस तर्क को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पी. ओ. ए. को विभिन्न उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया जाता है।

100. सूरज लैम्प्स एंड इंडस्ट्रीज (प्रा.) के मामले में लिमिटेड बनाम।

हरियाणा राज्य और अन्य [26]माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 4 में पी. ओ. ए. की प्रकृति पर विचार किया, जो कि नीचे दिया गया है:

> "4. पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 15-5-2009 [(2009) 7 SCC 363:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 126] ने इस तरह के एस. ए./जी. पी. ए./वसीयत लेन-देन (यानी काले धन का सृजन, भू-माफिया का विकास और नागरिक विवादों का अपराधीकरण) के दुष्प्रभावों को निम्नानुसार नोट किया:(एससीसी पीपी। 368-69, पैरा 19-21)
>
> "19. फ्रीहोल्ड संपत्तियों के संबंध में 'एसए/जीपीए/वसीयत' लेनदेन का सहारा लिया जाता है, भले ही ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण या हस्तांतरण के संबंध में कोई निषेध या निषेध न हो, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा:
>
> (a) अपूर्ण उपाधि वाले विक्रेता जो परिवहन के पंजीकृत कार्यों को निष्पादित नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
>
> (b) ऐसे खरीदार जो लेनदेन के किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड के बिना अचल संपत्तियों में अघोषित संपत्ति/आय का निवेश करना चाहते हैं। यह आदेशिका उन्हें निहित संपत्ति के रूप में खुलासा किए बिना किसी भी संख्या में संपत्तियों को रखने में सक्षम बनाती है।
>
> (c) खरीदार जो जानबूझकर या गलत सलाह पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से बचना चाहते हैं।जो व्यक्ति अचल संपत्ति में सौदा करते हैं, वे अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए कई स्टाम्प शुल्कों/पंजीकरण शुल्कों से बचने के लिए इन तरीकों का सहारा लेते हैं।
>
> *20.* इरादा चाहे जो भी हो, एस. ए./जी. पी. ए./विल लेनदेन के परिणाम परेशान करने वाले और दूरगामी हैं, जो अर्थआदेश, नागरिक समाज और कानून और आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।सबसे पहले, यह बड़े पैमाने पर आयकर, धन कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की चोरी को सक्षम बनाता है जिससे सरकार और जनता को इस तरह के राजस्व का लाभ नहीं मिलता है।दूसरा, इस तरह के लेन-देन अघोषित संपत्ति/आय वाले व्यक्तियों को अपने काले धन का निवेश करने और लाभ/आय अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे काले धन और भ्रष्टाचार के प्रसार को बढ़ावा मिलता है।
>
> *21.* इस तरह के लेन-देन के विनाशकारी संपार्श्विक प्रभाव भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार मूल्य बढ़ता है, तो कई विक्रेता (जिन्होंने बिना किसी विज्ञापन के बिक्री मुख्तारनामा को प्रभावित किया)

[26] (2012) 1 एस. सी. सी. 656

> पंजीकरण) इस तथ्य का लाभ उठाते हुए संपत्ति को पुनर्विक्रय करने के लिए लुभाया जाता है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में कोई पंजीकृत साधन या रिकॉर्ड नहीं है जिससे खरीदार को धोखा मिलता है। जब इस तरह की 'पावर-ऑफ-अटॉर्नी सेल्स' के तहत खरीदार को विक्रेता की कार्रवाई के बारे में पता चलता है, तो वह हमेशा इस मुद्दे को 'हल' करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाहुबलियों की मदद लेने की कोशिश करता है।दूसरी ओर, अचल संपत्ति माफिया कई बार ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो पहले से ही पावर-ऑफ-अटॉर्नी बिक्री के बशर्ते हैं और फिर पिछले 'पावर-ऑफ-अटॉर्नी बिक्री' खरीदारों को अपने अधिकारों का दावा करने से डराते हैं।किसी भी तरह से, इस तरह की पावर-ऑफ-अटॉर्नी बिक्री अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट माफिया के विकास और रियल एस्टेट लेनदेन के अपराधीकरण की ओर ले जाती है।"
>
> यह स्वामित्व सत्यापन और स्वामित्व के प्रमाणन को भी बनाता है, जो अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देन के व्यवस्थित संचालन का एक अभिन्न अंग है, मुश्किल, यदि असंभव नहीं है, तो अच्छे और विपणन योग्य स्वामित्व के आश्वासन के साथ संपत्ति के मालिक होने के इच्छुक प्रामाणिक खरीदारों को बुरे सपने दिखाता है।"

101. सूरज लैम्प्स एंड इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि "हमने केवल ध्यान आकर्षित किया है और इस सुव्यवस्थित कानूनी स्थिति को दोहराया है कि एसए/जीपीए/विल लेनदेन हस्तांतरण या बिक्री नहीं हैं और इस तरह के लेनदेन को सुविधा के पूर्ण हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

102. पी. ओ. ए. ने मेजर (सेवानिवृत्त) को कोई अधिकार नहीं दिया। नरेश गुप्ता। मेजर (सेवानिवृत्त) नरेश गुप्ता को कथानक में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

103. एक तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नहीं। 4 एक प्रामाणिक खरीदार है, इसलिए, उसके अधिकार T.P की खंड 53-A के तहत आरक्षित हैं। एक्ट करें। यह तर्क भी बहुत गलत है।

104. T.P की खंड 53-ए। अचल संपत्ति पर विचार के लिए हस्तांतरण के मामलों में अधिनियम लागू होता है।यह आंशिक प्रदर्शन के सिद्धांत पर आधारित है।तत्काल मामले में, D.P। नांगिया कभी नहीं

भूखंड का हस्तांतरण मेजर (सेवानिवृत्त) को किया था। नरेश गुप्ता।यह विचार के लिए स्थानांतरण नहीं है।केवल एक पी. ओ. ए. <आई. डी. 1> द्वारा निष्पादित किया गया था। मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में नांगिया। नरेश गुप्ता 07.01.1991।इसकी प्रकृति पी. ओ. ए. के रूप में बिना किसी हित के, बिना किसी विचार के बनी हुई है।D.P द्वारा एक एजेंसी बनाई गई थी। नंगिया और वह एजेंसी प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई थी, अर्थात् D.P। नंगिया, अनुबंध अधिनियम की खंड 201 को ध्यान में रखते हुए, जो इसके तहत है:

> "201. एजेंसी की समाप्ति।- किसी अभिकरण को प्रधान द्वारा अपने अधिकार को निरस्त करने; या अभिकरण के व्यवसाय को त्यागने वाले अभिकर्ता द्वारा; या अभिकरण के व्यवसाय को पूरा करने द्वारा; या प्रधान या अभिकर्ता के मरने या अस्वस्थ होने से; या प्रधान को दिवालिया देनदारों की राहत के लिए किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिवालिया घोषित किए जाने से समाप्त कर दिया जाता है।"

105. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि D.P की मृत्यु पर। 13.05.1998 पर नांगिया, मुख्तारनामा ने अपनी उपयोगिता खो दी थी।एजेंसी जिसे D.P द्वारा बनाया गया था। मेजर (सेवानिवृत्त) के साथ नांगिया नरेश गुप्ता 07.01.1991 पर मुख्तारनामा के निष्पादन के आधार पर 13.05.1998 पर समाप्त हो गए जब D.P। नांगिया की मृत्यु हो गई।पी. ओ. ए. के कहने पर उसके बाद किए गए किसी भी लेन-देन का कानून की नजर में कोई बल नहीं है।पी. ओ. ए. पोस्ट <आई. डी. 1> के बल पर निष्पादित कोई भी दस्तावेज़ शुरू से ही अमान्य है।यह प्रतिवादी सं. के पक्ष में किसी भी अधिकार को हस्तांतरित नहीं करता है। 4 राम गोपाल।

106. बहस यह भी दिया गया है कि एक पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर, विलेख को प्रतिवादी सं. 4, इसलिए जब तक विलेख रद्द नहीं किया जाता है, अधिकार हैं

प्रतिवादी सं. के साथ निहित किया गया।4. यह तर्क भी गलत है।

107. प्रत्यर्थी को जो भी अधिकार हैं, नहीं। 4 दावे, वह मेजर (सेवानिवृत्त) द्वारा से दावा करता है। नरेश गुप्ता, जिन्होंने कथित रूप से प्रतिवादी नं. 4 पी. ओ. ए. दिनांकित <आई. डी. 1> के बल पर।लेकिन, जैसा कि कहा गया है, मुख्तारनामा ने 13.05.1998 पर अपनी उपयोगिता खो दी थी जब D.P। नांगिया मर चुकी थी।इसलिए, 13.05.1998 के बाद, जैसा कि कहा गया है, पी. ओ. ए. के बल पर किया गया कोई भी लेनदेन अमान्य है।अतः, प्रतिवादी नं। 4 ऐसे किसी विलेख से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

<u>चाहे विवादित आदेश पराधिकरण के लिए बुरा हो, जिसने आदेश पारित किया था, वह भी संबंधित समय आक्षेपित पंजीकरणकर्ता के शुल्क को रोक रहा था</u>

108. वास्तव में, तीनों याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब अपील की सुनवाई की जा रही थी, तो उन्होंने एक आवेदन दायर किया जिसमें अधिकारी से अपील पर निर्णय नहीं लेने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उनके पास दोहरा प्रभार था-(i) पंजीयक का प्रभार और साथ ही (ii) सहकारी समितियों के सचिव का प्रभार।लेकिन, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अपीलीय प्राधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि वह अपने ही कार्यालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था।

109. तीनों याचिकाओं में, शुरू में प्रार्थना की गई थी कि आक्षेपित आदेशों को रद्द करते समय, मामले को रिमांड पर लिया जाए ताकि इसकी सुनवाई एक समर्थ, निष्पक्ष और समर्थ अधिकारी द्वारा की जा सके।इस दौरान

बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि वह मामले के रिमांड के लिए जोर देना नहीं डालते हैं।वह बहस के दौरान दिए गए आधारों पर आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए अपनी प्रार्थना को प्रतिबंधित करता है।

110. यह सच है कि कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।यह भी सच है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता है।लेकिन, तत्काल मामले में, सहकारी समितियों के सचिव द्वारा सुने गए आदेश हालांकि पंजीयक द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन वे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किए गए थे, जिन्होंने आक्षेपित आदेश पारित किए थे।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रासंगिक समय में सहकारी समितियों के सचिव के पास भी पंजीयक का प्रभार था।प्रशासन में, यह अक्सर होता है कि एक अधिकारी दो या तीन या उससे अधिक प्रभार रख सकता है, ऊर्ध्वाधर रूप से और साथ ही क्षैतिज रूप से।ऐसी स्थिति में, हालांकि ऐसा अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील को एक अलग क्षमता में नहीं सुन सकता है, लेकिन अगर वह किसी प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील सुनता है, जिसमें वह आरोप लगा रहा था, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी सुनवाई या निर्णय कानून के किसी भी सिद्धांत द्वारा खराब या दूषित है।इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई पर आपत्ति का वास्तव में कोई आधार नहीं था।

<u>प्लॉट का पुनरुत्थान</u>

111. प्रतिवादी की ओर से सं। 4, यह तर्क दिया जाता है कि सोसायटी द्वारा भूखंड को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक मूल्यवान अधिकार पहले से ही था।

प्रतिवादी सं. में निहित ।4. उसे एक हस्तांतरण विलेख के आधार पर भूखंड मिला; वह भूखंड का पूर्ण स्वामी है।

112. यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि प्रतिवादी नं। 4 ने भूखंड में कोई भी अधिकार या ब्याज प्राप्त नहीं किया क्योंकि लेनदेन D.P की मृत्यु के बाद हुआ था। डी. पी. नांगिया द्वारा निष्पादित पी. ओ. ए. के आधार पर कानून के तहत नांगिया की अनुमति नहीं थी।

113. यह प्रतिवादी नं. की ओर से तर्क दिया गया है। 4 कि संपत्ति का अधिकार उपनियमों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है और कोई भी उपनियम, जो भूखंड को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है, वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

114. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सोसायटी के उपनियम 50 और *51* में अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह प्रावधान है कि एक सदस्य जिसे भूखंड आवंटित किया गया है, वह आवंटन की तारीख से तीन साल के भीतर घर का निर्माण पूरा कर लेगा।तीन साल की इस अवधि को पंजीयक द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि विस्तारित अवधि तीन साल से अधिक नहीं हो सकती है।यदि तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण नहीं किया जाता है तो उपनियम 51 परिणाम देता है।उपनियम 51 के अनुसार, यदि तीन साल के भीतर निर्माण नहीं किया जाता है, तो प्रबंधन समिति के पास भूखंड को फिर से शुरू करने का अधिकार होगा।

115. भूखंड शुरू में R.S को आवंटित किया गया था। चुग, जिसने इसे D.P में स्थानांतरित कर दिया था। 28.09.1984 पर नांगिया।याचिकाकर्ता के अनुसार, D.P। नांगिया ने 26.06.1984 पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि

वह दो साल के भीतर घर का निर्माण करेगा, लेकिन उसने दस साल बाद भी घर का निर्माण नहीं किया।सोसायटी ने उन्हें 28.02.1992 और 2002 के बीच 10 नोटिस दिए।D.P नांगिया ने मेजर (सेवानिवृत्त) के पक्ष में पी. ओ. ए. को निष्पादित किया। नरेश गुप्ता 07.01.1991 पर, लेकिन D.P पर। नांगिया की मृत्यु 13.05.1998 पर हुई।अपने जीवनकाल में, D.P। नांगिया ने घर नहीं बनाया था।D.P की मृत्यु के बाद। नांगिया, प्रतिवादी नं। 4 ने मेजर (सेवानिवृत्त) से पी. ओ. ए. के बल पर अपने नाम पर भूखंड प्राप्त किया। नरेश गुप्ता।यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि पी. ओ. ए. ने <आई. डी. 1> पर अपनी उपयोगिता खो दी थी जब <आई. डी. 2>। नांगिया की मृत्यु हो गई थी और 13.05.1998 के बाद, पी. ओ. ए. के बल पर किया गया कोई भी लेनदेन अमान्य है।अत:, प्रतिवादी नं। 4 राम गोपाल को 13.05.1998 के बाद निष्पादित किसी भी विलेख से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

116. इस न्यायालय ने यह भी माना है कि वास्तव में, उपनियम कानून नहीं हैं।वे एक सहकारी समिति के सदस्यों के बीच इकरारनामा हैं।D.P। नांगिया समाज की सदस्य थीं।उन्होंने खुद को उपनियमों से बांध लिया था।उप-कानून 50 और 51 के तहत आवंटित भूखंड पर घरों के निर्माण के संबंध में हस्तांतरण या विनियमन पर प्रतिबंध स्वयं लगाया गया प्रतिबंध है।समाज के सदस्य समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के ठीक होना अपनी गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं।ये समझौते कानून के खिलाफ नहीं होने चाहिए।यदि ऐसा है, तो यह शून्य हो जाता है।लेकिन, उपनियम 50 और 51 के तहत बताए गए ये स्व-लगाए गए प्रतिबंध अमान्य नहीं हैं।वे किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हैं।वे वास्तव में समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रबंधन समिति द्वारा फिर से शुरू करने की शक्ति

कानून की नजर में समाज बुरा है।ये बुरा नहीं है।यह समाज के सदस्यों के बीच एक इकरारनामा है, जिसमें कानून की शक्ति है।प्लॉट को फिर से शुरू करके, याचिकाकर्ता ने कोई गलती नहीं की।प्लॉट को फिर से शुरू करना कानून के अनुसार है।

निष्कर्ष

117. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलीय प्राधिकारी ने पंजीयक के आदेशों को बनाए रखने में कानून की त्रुटि की है।पंजीयक के आदेश कानून के अनुसार नहीं हैं।इसलिए, तीनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए।

118. लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 के 1100 की अनुमति है।दिनांक 18.04.2015 का आक्षेपित आदेश, साथ ही, दिनांक 28.11.2002 का पंजीयक का आदेश (पत्र सं. 693/विधि Ni.Sa.Sa./2002 दिनांकित 28.11.2002) को रद्द गया है।

119. लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1101 स्वीकृत है।दिनांक 18.04.2015 का आक्षेपित आदेश, साथ ही, दिनांक 27.11.2002 का पंजीयक का आदेश (पत्र सं. 689/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक <आईडी1>) को रद्द गया है।

120. लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2015 का 1102 स्वीकृत है।दिनांक 18.04.2015 का आक्षेपित आदेश, साथ ही, दिनांक 28.11.2002 का पंजीयक का आदेश (पत्र सं. 692/विधि/नी. सा. सा./2002 दिनांक <आईडी1>) को रद्द गया है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)

अवनीत/05.05.2021